



वोट कटे, राज ठाकरे



दो बजे दोपहर

महाराष्ट्र का राण




मतदाताओं से अपील

विधानसभा चुनाव आपके लिए एक अवसर है राज्य को गढ़ने का सवाल है। आपसे अपील है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्पष्ट मतदान जरूर करें और राजी-नामिदियों को भी प्रेरित करें।

1 भाजपा ने गोपाल शेटी को मनाया **2** कांग्रेस की मधुरिमा ने नाम वापस लिया **3** मराठा आरक्षण आंदोलन के मनोज जरांगे भी हटे

साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों पर 4140 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। इस चुनाव में 7078 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए थे। जिसमें से 2938 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा वापस ले लिया है। सोमवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कुल 3237 उम्मीदवार उतरे थे। इस चुनाव में मुंबई की 36 सीटों पर कुल 420 प्रत्याशी उतरे हैं। इसमें मुंबई शहर की 10 सीटों पर 105 प्रत्याशी और मुंबई उपनगर की 26 सीटों पर 315 प्रत्याशियों का समावेश है। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन सत्तारूढ़ महायुति और विपक्ष के गठबंधन महाविकास आघाड़ी को बागी उम्मीदवारों से नामांकन वापस करवाने को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ी।

बागियों को संभालने के लिए दोनों गठबंधनों के बड़े नेता उतरे

तय हो गए चुनावी महाभारत के महायोद्धा

इन उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया



इन्होंने वापस नहीं लिया नामांकन

- बीड में शिव संग्राम पार्टी की ज्योति मेटे चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई हैं, उन्होंने अपना पर्चा वापस नहीं लिया है।
- शिवंदी ग्रामीण सीट से भाजपा की बागी नेता रनेहा पाटिल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने नामांकन पत्र वापस नहीं लिया है। इससे शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार शांताराम मोरे की परेशानी बढ़ सकती है।
- बीड के आष्टी विधानसभा क्षेत्र में चतुर्भुज मुकाबला होगा। भाजपा के बागी भीमराव थोडे चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं।
- माजलगांव में एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता रमेश आडसकर की बगावत जारी है।
- पुणे की पार्वती सीट से कांग्रेस के बागी नेता आबा बागुल ने पर्चा वापस नहीं लिया है।
- करबा पेंड से कांग्रेस के बागी कमल विहावास चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं।
- शिवाजीनगर से कांग्रेस के बागी नेता मनीष आनंद ने पर्चा वापस नहीं लिया है।

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बगावत से जूझ रहे दोनों गठबंधनों महायुति व महा विकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं ने नाम वापसी के आखिरी दिन बागी उम्मीदवारों को संभालने के लिए मोर्चा संभाला। कई सीटों पर दोनों गठबंधनों को सफलता भी मिली। भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेटी चुनाव मैदान से हट गए हैं, तो कांग्रेस की मधुरिमा राजे छत्रपति ने भी नाम वापस ले लिया है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने भी नाम वापस ले लिया है। नाम वापसी के आखिरी दिन भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति व कांग्रेस के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी ने पूरा जोर लगा दिया। गोपाल शेटी और मधुरिमा राजे जिसे चुनाव के प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल थे, लेकिन दोनों ने नामांकन वापस ले लिया। हालांकि, पार्टी नेतृत्व के दबाव के बावजूद मुंबई के माहिम से शिवसेना उम्मीदवार सदा सरवणकर ने अपना नाम वापस नहीं लिया।

उनका मुकाबला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित से होगा। गोपाल शेटी को मनाने के लिए भाजपा महासचिव विनोद तावडे को मैदान में उतरना पड़ा। दोनों लंबे समय से मित्र हैं और उनके समझाने के बाद शेटी मान गए। भाजपा ने दावा किया है कि उसके गठबंधन के कई बागी पीछे हट गए हैं। हालांकि, अभी लगभग एक दर्जन बागियों से संपर्क नहीं हो सका है। अब उनको अधिकृत उम्मीदवार के समर्थन के लिए मनाया जाएगा।

जरांगे समर्थक भी पीछे हटे

राज्य में एक बड़ा बदलाव मराठा आरक्षण आंदोलन के मनोज जरांगे के चुनाव मैदान से हटने से आया है। उन्होंने अपने समर्थक लगभग एक दर्जन अन्य उम्मीदवारों से भी मैदान से हटने को कहा है। किसी भी दल द्वारा सहयोग न करने से वह पीछे हटे हैं और कहा है कि मराठा समुदाय अपने विवेक से आरक्षण का समर्थन करने वाले का समर्थन करे। माना जा रहा है कि इससे महा विकास आघाड़ी को लाभ हो सकता है।

उद्धव ने दी चेतावनी

विपक्षी महा विकास आघाड़ी के भी एक दर्जन से ज्यादा बागी मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि, शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे ने अपने बागियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कांग्रेस के मुख्तार शेख ने पुणे के कखा पेट विधानसभा क्षेत्र से नामांकन वापस ले लिया और पार्टी के आधिकारिक

उम्मीदवार रवींद्र धांगेकर को समर्थन की घोषणा की। मधुरिमा कोल्हापुर उतर की चुनावी दौड़ से पीछे हटी हैं। वह पार्टी व गठबंधन की अधिकृत उम्मीदवार थीं, लेकिन बागी राजेश लटकर के पीछे न हटने से उन्होंने खुद ही आखिरी क्षणों में मैदान छोड़ दिया। कांग्रेस ने पहले लटकर को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में मधुरिमा को उम्मीदवार बनाया। इससे नाराज लटकर ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। अब लटकर निर्दलीय आघाड़ी समर्थित उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे।

जरांगे समर्थक भी पीछे हटे

राज्य में एक बड़ा बदलाव मराठा आरक्षण आंदोलन के मनोज जरांगे के चुनाव मैदान से हटने से आया है। उन्होंने अपने समर्थक लगभग एक दर्जन अन्य उम्मीदवारों से भी मैदान से हटने को कहा है। किसी भी दल द्वारा सहयोग न करने से वह पीछे हटे हैं और कहा है कि मराठा समुदाय अपने विवेक से आरक्षण का समर्थन करने वाले का समर्थन करे। माना जा रहा है कि इससे महा विकास आघाड़ी को लाभ हो सकता है।

यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीख बदली महाराष्ट्र DGP रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर

14 सीटों पर अब 13 की जगह 20 नवंबर को वोटिंग

एजेंसी | नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीटों पर अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीखों में बदलाव भाजपा, कांग्रेस, RLD और बसपा की मांग पर की गई है।



त्योहारों की वजह से शेड्यूल बदला

इन पार्टियों का कहना था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरुनानक देवजी का प्रकाश पर्व है। वहीं, केरल में 13 से 15 नवंबर तक कलपाथि रास्थोलसेवम मनाया जाएगा। इससे वोटिंग पर असर पड़ता।

20 नवंबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा की 38 और झारखंड की 38 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड लोकसभा और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर इसी दिन उपचुनाव है।

विपक्ष की शिकायत पर EC ने की कार्रवाई

विवेक फनसालकर को मिला अतिरिक्त प्रभार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया है। रश्मि शुक्ला के तबादले के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर को सोमवार को राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक का

फनसालकर को अतिरिक्त प्रभार

चुनाव निकाय ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह शुक्ला का प्रभार कैडर के अगले सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंप दें। अधिकारी ने बताया कि तदनुसार, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी फनसालकर को नए राज्य पुलिस प्रमुख की नियुक्ति होने तक डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह दूसरी बार है जब फनसालकर को राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस देखने आएंगे लोग: अश्विन वैष्णव

अरुण लाल | मुंबई

रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने सोमवार को मुंबई में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हम राष्ट्र निर्माण के मिशन मोड में जुटे हुए हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को इतना बेहतरीन बना रहे हैं कि यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय हेरिटेज में से एक होगा। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में 164605 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर रहे हैं। हम रेल यात्रा को सुविधाजनक व सुरक्षित बनाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले रेल बजट 1171 करोड़ हुआ करता था। इससे ज्यादा तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के रीडवलपमेंट में लगा रहे हैं।



मंत्री ने ली सेल्फी

रेल मंत्री ने पत्रकारों के साथ हंसी मजाक करते हुए सेल्फी ली। उन्होंने कहा कि पत्रकार बड़ी मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि पत्रकार हमेशा सही काम करते हैं।

टर्मिनस पर होंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

रेल मंत्री ने रेल अधिकारियों व कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि हमारे लोग मिशन मोड में काम कर रहे हैं। रात दिन देखे बिना राष्ट्र के सेवा में लगे हुए लोग रेल की कायापालट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए हम तेजी से मुंबई व महाराष्ट्र के कई टर्मिनस का रीडवलपमेंट कर रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से तैयार रेलवे स्टेशन देश का गर्व बनेंगे।

सिद्धरमैया को मूमि घोटाले में लोकार्युक्त पुलिस का समन

एजेंसी | मैसूर

लोकार्युक्त पुलिस ने मैसूर शहर विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में पुष्पाक्ष के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बुधवार को तलब किया है। इससे पहले लोकार्युक्त पुलिस ने 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती से पुष्पाक्ष की थी। वह भी मामले में आरोपी हैं। लोकार्युक्त के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार मुख्यमंत्री को समन जारी किए जाने की पुष्टि की। समन पर सिद्धरमैया ने कहा कि वह पुष्पाक्ष के लिए जा रहे हैं। सिद्धरमैया एमयूडीए से उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंडों के आवंटन में अनियमितता के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

हर ट्रेन में होंगे 6 जनरल डिब्बे

रेल मंत्री ने डीबीडी से बात वीत में कहा कि हम हर तरह के लोगों के लिए रेल सेवाएं बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने वंदे भारत चलाई और इसके



अलावा सारी सुविधाओं से भरी 2 ट्रेनें चलाई। हमारा प्रयास है कि देश की सभी ट्रेनों में जनरल यात्रियों के लिए 6 डिब्बे हों। मंत्री ने बताया कि इसके लिए हमने 12 सी 50 डिब्बे बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसमें से मार्च तक 2 हजार 500 डिब्बे रेल में लग जाएंगे। इसके बाद दिसंबर तक सभी ट्रेनों में जनरल के 6 डिब्बे करने की योजना पर काम किया जा रहा है।

बीजेपी कितनी सीटों पर जीतेगी

हंसते हुए, मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ, पर यह तय है कि हम सरकार बना रहे हैं। मैं यहाँ महायुति की सरकार की बात कर रहा हूँ। पिछले 3 से 4 महीने में हमारे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा है। जनता ने हमारे काम को सराहा है। अगर आप लोकसभा के रिजल्ट पर बात कर रहे हैं तो मैं बता दूँ कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। विधानसभा चुनाव लोकल होता है, और नगरसेवक का चुनाव उससे भी लोकल होता है।

16 हजार 240 करोड़ की पटरियां

रेल मंत्री ने कहा कि हम मुंबई के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए 301.5 किमी की नई पटरियां बिछाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम 16 हजार 240 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अश्विन वैष्णव ने कहा कि इन नए पथ के बन जाने के बाद मुंबई में यातायात और बेहतर होगा।

मीरा भाईंदर में निर्दलीय बिगाड़ेंगे समीकरण BJP, कांग्रेस और गीता जैन में होगा त्रिकोणीय मुकाबला

डीबीडी संवाददाता | भाईंदर

मुंबई की मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद कुल 17 उम्मीदवार बचे हैं। अब इस सीट पर 17 प्रत्याशियों की चुनावी भिड़त होने वाली है। अंतिम दिन नामांकन वापस लेने वालों में बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता की पत्नी सुमन मेहता, पूर्व बीजेपी पार्षद सुरेश खंडेलवाल, चंद्रकांत मोदी, बहुजन विकास आघाड़ी की उम्मीदवार प्रीडा मोरास, एजाज खतीब और रमजान खत्री का नाम शामिल है। जिन 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं उनमें से 4 उम्मीदवारों ने बीजेपी के समर्थन में तो प्रीडा और खत्री ने कांग्रेस के

समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया है। मीरा भाईंदर विधानसभा सीट से अब महायुति से बीजेपी के नरेंद्र मेहता, महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन, मनसे से संदीप राणे, बसपा से कालीचरण हरिजन चुनावी मैदान में है। इसके अलावा राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्वराज्य सेना से अरुण कुमार खंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) से अरुणा चक्रे, हिंदू समाज पार्टी से सुरेन्द्र कुमार जैन, सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी से सत्य प्रकाश चौरसिया और विधायक गीता भरत जैन, पूर्व नगराध्यक्ष अरुण कदम, पूर्व नगरसेवक हंसुकुमार पांडे और अन्य 6 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।



महायुति धर्म के पालन का किया वादा

बीजेपी के नरेंद्र मेहता और महायुति के घटक दल शिंदे शिवसेना के प्रताप सरनाईक के बीच विगत कुछ वर्षों से रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं। बीजेपी के पदाधिकारियों का हमेशा से ही यह आरोप रहा है कि शिवसेना महायुति धर्म का पालन नहीं करती है और बीजेपी के पदाधिकारियों को दबाने की राजनीति करती है।

गीता, मेहता और हुसैन में त्रिकोणीय मुकाबला

मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर अब सीधे-सीधे वर्तमान विधायक और निर्दलीय उम्मीदवार गीता भरत जैन, बीजेपी के नरेंद्र मेहता तथा कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के पूर्ण आसार हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने खुलकर निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन का समर्थन किया था। इस बार के चुनाव में विभाजित शिवसेना के उद्वेग शिवसेना का समर्थन कांग्रेस को और शिंदे शिवसेना का समर्थन बीजेपी को है। जिससे इस सीट पर त्रिकोणीय कांटे की टक्कर निश्चित है।

महायुति के दलों ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस

सोमवार को महायुति के सभी घटक दलों ने मिलकर एक संयुक्त पत्रकार परिषद बुलाई थी। जिसमें शिवसेना से विधायक प्रताप सरनाईक, बीजेपी से नरेंद्र मेहता, रवि ब्यास, आरपीआई (आठवले) से देवेंद्र शेलकर, एनसीपी से आसिफ शेख तथा सभी दलों के पदाधिकारी मौजूद थे।

निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं हार जीत का समीकरण

वहीं दूसरी तरफ देखें तो अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के दम पर चुनाव जीतने की क्षमता तो नहीं नजर आ रही, लेकिन वोट काटकर वे चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के हार जीत का समीकरण बिगाड़ने की ताकत अवश्य रखते हैं। कुल मिलाकर देखें तो मनसे के संदीप राणे बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कुछ हद तक वोट काटेंगे। निर्दलीय हंसुकुमार पांडे कई वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, लेकिन उत्तर भारतीय होने के नाते वे भी कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पूर्व उपनगराध्यक्ष अरुण कदम की पकड़ हर समाज के लोगों पर रही है और वैसे भी कदम सभी मुख्य राजनीतिक दलों में पदाधिकारी रहे हैं, तो वे भी कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय गीता जैन के वोट भी काट सकते हैं।

कार्यकर्ताओं को जमीनीस्तर पर काम करने कहा

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरनाईक ने मीरा भाईंदर विधानसभा से नरेंद्र मेहता और ओवला मजीवाड़ा विधानसभा से खुद के लिए सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को जमीनीस्तर पर कार्य करने का आवाहन किया। बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मेहता ने भी मीरा भाईंदर के विकास के लिए 44 संकल्प लेने का वचन दिया। रवि ब्यास ने स्थानीय स्तर के मतभेद भिंटकर पार्टी द्वारा दिए गए उम्मीदवार मेहता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया और महायुति के सभी घटक दलों ने युति धर्म के पालन का वादा किया।

हेलीकॉप्टर से AB फार्म भेजना पड़ा महंगा निवार्चन आयोग ने दिए जांच के आदेश

डीबीडी संवाददाता | नासिक

नासिक जिले में विधानसभा की 3 सीटों के लिए विशेष विमान द्वारा लाए गए 'एबी फॉर्म' की खबर के बाद चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। आयोग ने जिला प्रशासन को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से इस संबंध में जानकारी मांगी है। इसके बाद प्रत्याशियों में खलबली मची है। निवार्चन आयोग ने इस मामले में जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की धूम



मची हुई है। नासिक जिले में गठबंधनों और पार्टियों के भीतर बगावत और मित्रतापूर्ण लड़ाई का नया अध्याय शुरू हो गया है। वहीं नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन 'एबी फॉर्म' को लेकर नाटकीय घटनाएं

घटीं। देवलीली और दिंडोरी में एक-एक उम्मीदवार के लिए विशेष विमान से 'एबी फॉर्म' भेजा गया। अंतिम कुछ मिनटों में यह दाखिल होने से उम्मीदद्वारी पर अधिकारिक मुहर लग गई। इगतपुरी के लिए एक 'एबी फॉर्म' दस मिनट देर से आया, जिससे वह दाखिल नहीं हो सका। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने जिला निवार्चन शाखा से जानकारी मांगी है। आयोग ने पूछा है कि विमान किसने बुलाया, इसमें कौन थे, किन उम्मीदवारों के लिए फॉर्म मंगाए गए और इसके लिए कितना खर्च हुआ।

एयर ट्रैफिक कंट्रोल विभाग से मांगी जानकारी

निवार्चन आयोग के आदेश के बाद नासिक जिला प्रशासन ने लेंकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल विभाग से जानकारी मांगी है। आयोग जांच शुरू कर दी है और हेलीकॉप्टर से एबी फॉर्म भेजने को ने जिला प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

उम्मीदवारों के खातों में जुड़ेंगे खर्च

विमान से यात्रा का खर्च उम्मीदवार के फॉर्म के लिए हुआ, तो है, लेकिन यदि यह खर्च उम्मीदवार के खाते में आता है, तो यह खर्च उम्मीदवार के खाते में जाएगा अन्यथा, यह खर्च पार्टी विमान किराए पर लेने का खर्च अधिक होगा। इससे संबंधित के खाते में जा सकता है। पार्टी के खर्च पर कोई सीमा नहीं उम्मीदवारों के आगे के खर्च पर बड़ी समस्याएं आ सकती हैं।

अजीत पवार के बागी उम्मीदवार भ्रष्टाचार व अपराध को दूर भगाएंगे

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

प्रदेश में शरद पवार से अलग हुए अजीत पवार की राकांपा पार्टी से उल्हासनगर में महायुति से बगावत कर भरत (गंगोत्री) राजवानी ने अपक्ष चुनाव लड़ने के लिए फार्म भरा है। गंगोत्री ने सोमवार को आखिरी दिन होते हुए भी फार्म वापस नहीं लिया और चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। गंगोत्री ने बताया कि वे चुनाव उल्हासनगर से अपराध व भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। उल्हासनगर में भ्रष्टाचार के चलते शहर की सड़कों के कारण लोगों व वाहन चालकों का जीना हो गया है। लोगों को उनकी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं शांति के चलते अपराध चरम पर पहुंच गया



है। जिसे रोकने में प्रशासन फेल है। शहर में विरोधी अफवाह फैला रहे थे कि गंगोत्री पचास वापस ले लेंगे। परंतु गंगोत्री ने पचास वापस न लेकर विरोधियों के आकलन व अफवा पर पानी फेर दिया है। उल्हासनगर से राकांपा अजीत पवार की पार्टी से शहर अध्यक्ष गंगोत्री ने अपक्ष पचास भर शहर में भ्रष्टाचार व अपराध रोकने में फेल भाजपा के पूर्व विधायक कुमार आयलानी व ओमि कालानी के खिलाफ अपना चुनावी बिगुल बजाया है। गंगोत्री ने महायुति से बगावत कर महायुति

के अधिकृत उम्मीदवार भाजपा के कुमार आयलानी के खिलाफ आरोप लगाते हुए फार्म वापस न लेते हुए चुनावी मैदान में हैं। भरत गंगोत्री के द्वारा अपराध व भ्रष्टाचार को उल्हासनगर से खत्म करने के मुद्दे पर उल्हासनगर के राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं के साथ ही उपहास शुरू है कि जिस पार्टी के गंगोत्री सदस्य व शहर अध्यक्ष हैं अब वह शहर को कालानी व आयलानी मुक्त विकास की नयी गति के नारे के साथ मैदान में डटे हुए हैं।

मतदाता को असुविधा नहीं हो इसके लिए मतदान केंद्रों पर सभी सुविधा हो: अशोक शिंगारे

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

विधानसभा चुनाव 2024 के लिए ठाणे जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 120 नवंबर को मतदान प्रक्रिया के लिए जिले की 18 विधानसभा चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए किये गए सुविधाओं का निरीक्षण जिला चुनाव निर्णय व जिलाधिकारी अशोक शिंगारे ने निरीक्षण किया। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो इसके लिए सभी लोगों को जिम्मेदारी गंभीरता से लेने के लिए निर्देश दिया। जिलाधिकारी कार्यालय पर समिति सभागृह में जिला चुनाव निर्णय व जिलाधिकारी अशोक शिंगारे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक

में उपजिला चुनाव अधिकारी वैशाली माने, मनपा नगर अभियंता सहित 18 विधानसभा के अभियंता उपस्थित थे। ठाणे मनपा क्षेत्र के अंतर्गत 1 हजार 546 मतदान केंद्र, कल्याण डोंबिवली मनपा क्षेत्र के अंतर्गत 1 हजार 261 मतदान केंद्र, ग्रामीण भागों में 1 हजार 124 मतदान केंद्र, नवी मुंबई मनपा क्षेत्र के अंतर्गत 831 मतदान केंद्र, मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्र के अंतर्गत 755 मतदान केंद्र, शिवडी मनपा क्षेत्र के अंतर्गत 586 मतदान केंद्र, उल्हासनगर मनपा क्षेत्र के अंतर्गत 399 मतदान केंद्र, साथ ही सभी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत 453 मतदान केंद्रों के सुविधाओं की जवाबदारी सभी महानगरपालिका व नगरपालिका

को है और प्रमोण इलाकों के मतदान केंद्रों की जिलापरिषद की पथ निर्देश जिला चुनाव निर्णय अधिकारी शिंगारे ने दिया। जिले की 18 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता के लिए सूचना फलक, दिशादर्शक, दिव्यांगों के लिए रैप की सुविधा, मतदाता सहायता केंद्र, मंडप व्यवस्था, पीने के लिए पानी की सुविधा, प्रतिकालीन, मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता के लिए कुर्सी की व्यवस्था, मतदान केंद्र के नजदीक मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था, प्रथमोपचार सुविधा, मतदान केंद्र पर पालना घर, दिव्यांग के लिए व्हीलचेयर की सुविधा की व्यवस्था के लिए बैठक में निर्देश दिया।

मनोज जरांगे का यू टर्न

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मराठा आरक्षण के लिए लगातार आंदोलन कर रहे मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने विधानसभा चुनाव से हटने का बड़ा फैसला किया है। जरांगे ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि एक जाति से जीतना संभव नहीं है क्योंकि लिस्ट ही नहीं आई है। हालांकि, अगर वे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो क्या वे उम्मीदवार छोड़ देंगे? जरांगे ने इस संबंध में अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। जरांगे ने चुनाव नहीं लड़ने के पीछे की वजह भी बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव से पीछे हटने की घोषणा करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मैं किसी के दबाव में पीछे नहीं हटा हूँ। न तो मैं चुनाव में किसी को चुनने के लिए कहने जा रहा हूँ। मैं किसी को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन

अगर कोई मेरे आंदोलन से जुड़ेगा तो मैं कार्यक्रम करूंगा। जरांगे पाटिल ने कहा है कि मराठा समुदाय का आंदोलन जारी रहेगा। हर घर में मराठा हैं, चाहे वे चुनाव प्रक्रिया में हो या नहीं। हमारे पीछे हटना का तो स्वावल ही नहीं है। ये आंदोलन जारी रहेगा थमने वाला नहीं है। जरांगे पाटिल ने कहा कि हम किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं। इनमें उम्मीदवारों को अपना अपना आवेदन वापस ले लेना चाहिए। चाहे महा विकास आघाड़ी हो या महायुति, दोनों पक्षों के नेता एक ही हैं। इनमें से कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। हमें किसी के पक्ष में प्रचार भी नहीं करना है और न ही वोट को लेकर किसी प्रकार की कोई सभा करनी है। मेरे ऊपर किसी भी पार्टी का कोई दबाव नहीं था। मेरे पीछे हटने का तो कोई स्वावल ही नहीं, मैं बस चुनाव से पीछे हटा हूँ।

जीएलआर इंडिया द्वारा डी.बी.शंकर के सहयोग ड्राइवरों के लिए स्वास्थ्य शिविर

डीबीडी संवाददाता | भिवंडी

नई दिशा परियोजना अंतर्गत जर्मन लेप्रोसी एंड टीबी रिलीफ एसोसिएशन इंडिया (जीएलआरए इंडिया) द्वारा डी.बी.शंकर के सहयोग से अंजुर इंडियन ऑईल पेट्रोलंपंप, मानकोली भिवंडी में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ट्रक ड्राइवरों, सहायकों और संबंधित समुदायों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था, जो अक्सर अपने व्यस्त यात्रा कार्यक्रम के कारण चिकित्सा



सुविधाओं तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। जीएलआरए इंडिया पिछले 9 महीनों से भिवंडी में ट्रक चालक समुदाय के लिए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू कर रहा

है। संगठन का लक्ष्य ट्रक चालक समुदाय को स्वस्थ और सशक्त बनाना, उन्हें टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक करना और समय पर इलाज कराना

है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ट्रक ड्राइवरों और उनके सहायक द्रक चालक समुदाय के लिए एक विशेष स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें टी बी के लक्षण, उपचार और रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया गया। डीबी शंकर के सहयोग से जीएलआरए इंडिया द्वारा संचालित 'नई दिशा' परियोजना ने स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से ट्रक ड्राइवरों और उनके सहयोगियों को टीबी के बारे में जागरूक करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया।

आवश्यकतानुसार दवाएं भी दी गईं। स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ ट्रक चालक समुदाय के लिए एक विशेष स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें टी बी के लक्षण, उपचार और रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया गया। डीबी शंकर के सहयोग से जीएलआरए इंडिया द्वारा संचालित 'नई दिशा' परियोजना ने स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से ट्रक ड्राइवरों और उनके सहयोगियों को टीबी के बारे में जागरूक करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया।

उल्हासनगर में दिल दहलाने वाली घटना सुरक्षा गार्ड ने चार साल की बच्ची से की घिनौनी हरकत

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

उल्हासनगर शहर के दशहरा मैदान परिसर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है। जिसमें एक 17 साल के सिक्वोरिटी गार्ड ने उसी बिल्डिंग में रहने वाली चार साल की बच्ची से छेड़छाड़ की। इस घटना से लोगों में बड़ी नाराजगी है। पुलिस ने पॉसटो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिंसात में ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़की मूल रूप से नेपाल की रहने

वाली है और अपने माता-पिता के साथ उल्हासनगर शहर में रहती है। उसके पिता उसी बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं। आरोपी 17 वर्षीय युवक भी उसी इमारत में दिन के समय सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। वह राजस्थान राज्य का रहनेवाला है, और उनका परिवार भी कई वर्षों से उल्हासनगर में रह रहा है। और आरोपी दिन में गुब्बारे बेचने का भी काम करता है। शनिवार दोपहर किशोरी घर में अकेली थी। उसके माता-पिता काम

के सिलसिले में बाहर गए थे। मौका पाकर आरोपी लड़की के घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक निवासी ने दरवाजा बंद होने का संदेह होने पर दरवाजा खोला। तभी उन्होंने बच्ची को रोते हुए देखा। निवासियों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित लड़की को सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच की गई। जांच रिपोर्ट में यौन शोषण की बात सामने आई।

सुप्रीम कोर्ट से सिडको को झटका शीर्ष न्यायालय ने कहा- बच्चों के लिए कुछ हरे-भरे मैदानों की जरूरत

डीबीडी संवाददाता | भिवंडी

नवी मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिडको) की याचिका खारिज कर दी, जिसमें नवी मुंबई में एक खेल परिसर के लिए निर्धारित भूमि को निजी बिल्डरों को पुनः आवंटित करने के महाराष्ट्र सरकार के कदम के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने नवी मुंबई जैसे शहरी क्षेत्रों में हरित स्थानों को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। शहरी विस्तार के बीच खुले क्षेत्रों की घटती

उपलब्धता को रेखांकित करते हुए सीजेआई ने टिप्पणी की, हमें अपने बच्चों के लिए कुछ हरित स्थानों की आवश्यकता है, खासकर मुंबई जैसे शहरों में सीजेआई ने आगे कहा, ये कुछ बचे हुए हरे-भरे जगह हैं, और हमें इन्हें संरक्षित करना चाहिए। सिडको के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। उन्होंने बताया कि मॉल और आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए बिल्डरों को हरित क्षेत्र दिए गए थे। सीजेआई ने कहा कि नवी मुंबई के बच्चों को स्कूल से लौटने के बाद खेल खेलने के लिए पड़ोसी रायगढ़ जिले में कई किलोमीटर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकार ने खेल परिसर को रायगढ़ जिले के मानगांव में स्थानांतरित करने का भी फैसला



किया था, जो मौजूदा साइट से 115 किलोमीटर दूर है। पीठ ने पहले मुंबई और नवी मुंबई जैसे शहरों में बचे हुए कुछ हरित क्षेत्रों के संरक्षण पर जोर दिया था, जो केवल ऊर्ध्वाधर विकास देख रहे थे। नवी मुंबई में भूमि 2003 और 2016 में खेल परिसर के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन योजना प्राधिकरण

ने इसका एक हिस्सा आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए एक निजी डेवलपर को आवंटित कर दिया था। शीर्ष अदालत ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा था, सरकार बची हुई हरित जगहों पर घुसपैठ करती है और उन्हें बिल्डरों को दे देती है। सीजेआई ने आगे कहा, मुंबई और नवी मुंबई जैसे शहरों में बहुत कम हरित क्षेत्र बचे हैं। आगको उन्हे संरक्षित करना होगा और बिल्डरों को निर्माण, निर्माण, निर्माण और निर्माण करने के लिए नहीं देना होगा। पीठ को यह जानकर प्रथम दृष्टया आश्चर्य हुआ कि राज्य स्तरीय खेल परिसर के लिए बनाई गई भूमि को विकास के लिए आवंटित किया जा रहा था और प्रस्तावित सुविधाओं को रायगढ़

जिले में स्थानांतरित किया जाना था। पीठ ने आश्चर्य जताया कि खेल परिसर की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए 115 किलोमीटर की यात्रा कौन करेगा, जिससे कुछ वर्षों बाद उस भूमि का भी यही हश्र होने की आशंका है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नवी मुंबई में खेल परिसर के लिए बनाई गई भूमि का कोई हस्तांतरण नहीं होगा। जुलाई में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राज्य के निर्णय को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि खेलों ने लोगों और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोर्ट ने कहा था कि, यह सही समय है कि सरकार इसे व्यावसायीकरण और केंद्रीकरण मंत्र के बराबर महत्व दे।

महिला के पति की गैरकानूनी रूप से गिरफ्तारी के लिए सरकार देगी 1 लाख का मुआवजा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के गलत आचरण और सत्ता के दुरुपयोग की निंदा करते हुए महिला रत्ना वन्म को उनके पति चंद्रकांत की गैरकानूनी रूप से गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि व्यक्ति की गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण और सत्ता का दुरुपयोग थी और राज्य सरकार को गैरकानूनी गिरफ्तारी और परिवार को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा देने चाहिए। न्यायमूर्ति भारती डंगरे और मंजूषा देशपांडे की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष रत्ना वन्म की ओर से वकील सुविधा पाटिल की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि व्यक्ति की गिरफ्तारी उचित प्रक्रिया के बिना अनुचित प्रावधानों के तहत की गई थी। पीठ ने गहन जांच नहीं करने

के लिए मुंबई पुलिस की आलोचना की और गंभीर आरोपों के बावजूद दंपति द्वारा शिकायत करने पर आवश्यक हलफनामा दायर करने में विफल रहने के लिए जाधव पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधिकारियों को विवेकपूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और उचित कारण के बिना हिरासत में लेना अधिकारों का उल्लंघन है। यह देखते हुए कि चंद्रकांत वन्म की हिरासत शक्ति के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण थी। पीठ ने राज्य सरकार को वन्म को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे एपीआई जाधव सहित जिम्मेदार लोगों से वसूला जा सकता है। रत्ना वन्म की वकील सुविधा पाटिल ने दलील दी कि एपीआई जाधव के पास उनके पति और मन्ड्रों को बिना कारण गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं था। इसके अलावा जाधव ने

कथित तौर पर मामले को सुलझाने के लिए 10 हजार रुपए की रिश्तत मांगी थी। पीठ ने पाया कि पुलिस ने तथ्यों की पुष्टि किए बिना केवल महिला की शिकायत पर भरोसा किया था, जो पूर्वग्रह और कटाचार को दर्शाता है। सितंबर 2012 में दंपति ने वडाळा के सिद्धार्थ नगर में अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, जो भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसको लेकर उनकी पड़ोसी जगदीवी सुरकांत भगोडे ने मरम्मत की अनुमति दिलाते के नाम पर 20 हजार रुपए की मांग की और पैसे का भुगतान नहीं करने पर पुलिस करवाई के लिए अपने संबंधों का इस्तेमाल करने की धमकी दी। दंपति ने वडाळा टीटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) तुकाराम जाधव ने इसे बॉम्बे का मामला बताते हुए शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया।

बीवीए को मिलेगा सीटी चुनाव चिह्न

निर्वाचन आयोग ने बंबई हाई कोर्ट में दी दलील

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। सोमवार को नामांकन वापसी के बाद सभी सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या तय हो गई है। अब पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव चिह्न को लेकर दायर याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी।

सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सोमेश्वर सुंदरसन और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर



की पीठ ने बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा पार्टी को चुनाव चिह्न आवंटित करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई की। सोमवार को निर्वाचन आयोग ने बंबई हाई कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए जरूरी दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद हितैद्र ठाकुर के नेतृत्व वाली बहुजन विकास आघाड़ी (VBA) को सीटी चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा।

जनवरी में जनता दल (यू) को दिया था सीटी चुनाव चिह्न

बता दें कि इस साल जनवरी में निर्वाचन आयोग ने जनता दल (यूनाइटेड) को सीटी चुनाव चिह्न आवंटित किया था। महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट से बीवीए के उम्मीदवार ने 2024 का चुनाव सीटी चुनाव चिह्न पर लड़ा, क्योंकि जनता दल (यू) का कोई उम्मीदवार नहीं था। निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष जनता दल (यू) से प्राप्त एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें आयोग को 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया गया था।

जेडीयू ने वापस किया चुनाव चिह्न



जनता दल (यूनाइटेड) ने पत्र में कहा कि पार्टी 30 जनवरी 2024 के आदेश के आधार पर उसे आवंटित सीटी चुनाव चिह्न को वापस कर रही है। निर्वाचन

आयोग ने अदालत को बताया कि चूंकि बीवीए के याचिकाकर्ता ने सीटी चुनाव चिह्न के लिए आवेदन किया था, इसलिए इसे जरूरी नियमों/दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके पार्टी को आवंटित किया जाएगा। आयोग की दलील के बाद बंबई उच्च न्यायालय की पीठ ने बीवीए की याचिका का निपटारा कर दिया।

DBD

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पॉसिबिलिटी है

दो बजे दोपहर चुनाव से पहले अजित पवार की बड़ी राहत

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन अजित पवार की एनसीपी को बड़ी सफलता मिली है। महायुति में आपसी मतभेद के कारण एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे। लंबी बातचीत और आपसी सहमति के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अजित पवार गुट के खिलाफ उतारे दो उम्मीदवारों के नामांकन वापस लिए हैं। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन सोमवार को शिवसेना (शिंदे गुट) के दो उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से अविनाश हैबत राणे और दिंडोरी विधानसभा क्षेत्र से धनराज हरिभाऊ महाले ने चुनाव से अपने नाम वापस ले लिए।

शिवसेना के उम्मीदवारों ने दो सीटों से वापस लिए नामांकन



अजित पवार की अहम भूमिका

विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले यह एनसीपी और महायुति के लिए एक बड़ी मजबूती मानी जा रही है। अजित पवार ने इन दोनों उम्मीदवारों के नामांकन वापस करवाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे महायुति की चुनावी

दोनों सीटों पर NCP के उम्मीदवार

महायुति ने दिंडोरी विधानसभा सीट से एनसीपी ने वर्तमान विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अणुशक्ति नगर में एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दिया है। नवाब मलिक ने इस सीट का पांच बार प्रतिनिधित्व किया है।

संभावनाओं को और बल मिला है। इस राजनीतिक कदम ने अजित पवार की प्रभावशाली राजनीतिक समझ और सहयोगियों के साथ एकता बनाए रखने की उनकी क्षमता को उजागर किया है।

नवाब मलिक के खिलाफ शिवसेना ने उतारा उम्मीदवार

बता दें कि महायुति में शामिल बीजेपी ने अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध किया है। वहीं मलिक के

खिलाफ मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा सीट से एकनाथ शिंदे के शिवसेना ने अपना उम्मीदवार भी उतारा है। शिवसेना ने नवाब मलिक की बेटी

सना मलिक के खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा किया था। लेकिन अब बातचीत के बाद शिवसेना उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया है।

'पार्टी में फूट डालने वाले गदारों को सिखाएंगे खबक'

गिरीश महाजन ने बागियों को दी चेतावनी



डीबीडी संवाददाता | मुंबई/नासिक

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का सोमवार को आखिरी दिन था। महायुति और महाविकास अघाड़ी के कई बागियों ने सोमवार को नामांकन वापस लिया है। लेकिन कुछ बागियों ने अब भी शीर्ष नेतृत्व के प्रयासों के बाद भी नाम वापस नहीं लिए हैं। इन नेताओं को ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन ने सख्त चेतावनी दी है। गिरीश महाजन ने कहा कि जो लोग पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं और फूट डालते हैं, उन्हें आगे चलकर उन्हें सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह पार्टी के प्रति एकनिष्ठ हैं

और कभी भी समझौता नहीं किया है। इसलिए, उनका किसी भी बागी को समर्थन और आशीर्वाद नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति में कहीं भी बगावत नहीं होगी। नासिक में टिकट वितरण के बाद हुई नाराजगी दूर हो गई है और बागी व नाराज लोगों के साथ व्यक्तिगत चर्चा हुई है। इसके बाद 4 तारीख की नाम वापसी के बाद नाराज और बागी लोग महायुति के प्रचार के लिए एकजुट होंगे, ऐसा दावा किया गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल होने के बाद सोमवार को नाम वापस लिए गए। नासिक जिले में 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस बार महायुति में बड़े पैमाने पर बगावत हुई है।

विपक्ष ने किया झूठा प्रचार

बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने झूठे प्रचार किया था, जिससे महायुति को नुकसान हुआ, लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं और राज्य सरकार की अच्छी योजनाओं के कारण महायुति की सरकार फिर से बनेगी और मुख्यमंत्री भी महायुति का होगा।

महायुति एकजुट है

गिरीश महाजन नासिक में बागी और नाराज नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए खुद मौजूद थे। उन्होंने चर्चा के बाद पत्रकारों से कहा करते हुए दावा किया कि महायुति एकजुट है। महाजन ने कहा मैंने दो दिनों में हर किसी से बात की और पिछले समय में हुए अन्याय और शिकायतों को सुना। उन्होंने यह भी कहा कि महायुति के नेता अब एकजुट होकर चुनाव में उतरेंगे। गिरीश महाजन ने आश्वासन दिया

है कि आगे चलकर हर किसी को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब सभी लोग प्रचार में सक्रिय होंगे और भाजपा के विधायकों ने पिछली गलतियों को सुधारने का वादा किया है, जिससे कार्यकर्ताओं को अधिक मौके मिलेंगे। महाजन ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को बड़े पद दिए और फिर गद्दारी की, उन्हें आने वाले समय में कार्यकर्ता और मतदाता अपनी जगह दिखा देंगे।

डीजीपी के हटते ही फेल हो जाएगी महायुति सरकार की चुनावी चाल: वडेड़ीवार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता विजय वडेड़ीवार ने सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले के फैसले का स्वागत किया और कहा कि चुनावी गड़बड़ियों के माध्यम से चुनाव जीतने की महायुति सरकार की मंशा विफल हो गई है। हम चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेड़ीवार ने कहा कि उन्हें नियुक्त करने के लिए महायुति सरकार की क्या मजबूरी थी? उन्हें सेवा विस्तार देने की क्या जरूरत थी? इसका उद्देश्य यह था कि चुनाव परिणामों में न हो। वे विस्मयपूर्ण के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते थे। उनकी मंशा विफल हो गई है।



पवार साहब ने भी इस पर चिंता जतायी थी। हमने भी आयोग को इस पर दो पत्र भेजे थे। मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार ने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को यह स्वीकार करना चाहिए कि चुनाव आयोग (ईसी) निष्पक्ष है, क्योंकि रश्मि शुक्ला का तबादला उनके अनुरोध पर किया गया था और अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय लिया जाता है तो उन्हें यह दावा नहीं करना चाहिए कि चुनाव आयोग पक्षपाती है।

सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाली महिला को मुंबई पुलिस ने छोड़ा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

हाल ही में मुंबई पुलिस को एक संदेश मिला था जिसमें उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जांच के बाद मुंबई पुलिस ने धमकी भरा ईमेल भेजने वाली युवती को पकड़ लिया। मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने को लेकर पकड़ी गई 24 वर्षीय एक महिला को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।



पूछताछ के बाद छोड़ा

ठाणे जिले के उल्हासनगर में अपने परिवार के साथ रहने वाली आईटी स्नातक फातिमा खान को महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) और पुलिस के संयुक्त अभियान में पकड़ा गया था। अधिकारी ने बताया कि उसे पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया, नॉटिस दिया गया और बाद में रविवार को घर जाने दिया गया। पुलिस के मुताबिक फातिमा खान अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन मानसिक तौर पर अस्थिर है। उसके पिता लकड़ी का कारोबार करते हैं।

पुलिस ने दर्ज किया मृतक के खिलाफ पोक्सो का मामला

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

डीबी मार्ग इलाके में गुजरात के सूरत का एक व्यक्ति मुंबई के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसे जे जे अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृत शव के साथ एक नाबालिग लड़की की भी मौजूद थी। नाबालिग लड़की की शिकायत पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के पुलिस ने मृत शव के खिलाफ मामला दर्ज



किया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक यह घटना शनिवार को शाम करीब 6:15 बजे हुई, जब होटल सुपर के प्रबंधक ने अधिकारियों को सूचित किया कि एक अतिथि अपने कमरे में बेहोश पाया गया है।

क्या है मामला ?

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृत व्यक्ति की पहचान संजय कुमार रामजीभाई तिवारी (42) के रूप में हुई है और वह सूरत का रहने वाला है। पुलिस ने पुष्टि की कि मृतक की परिचित 14 वर्षीय लड़की भी उस समय होटल के कमरे में मौजूद थी। तिवारी की मौत के बाद पुलिस ने लड़की की मां से पूछताछ की, जिसने आरोप लगाया कि मृतक ने उसकी बेटी के साथ जबरन मारपीट की थी। इस बयान के आधार पर पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपों सहित आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज

डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की है और मृतक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 64(1), 65(1), 336(2), 336(3) और 340(2) के साथ-साथ पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 8 और 10 के तहत आरोप दर्ज किए हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इन्तजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक शव के मौत की असली वजह सामने आएगी।

पश्चिम रेलवे द्वारा मनाया गया 74वां स्थापना दिवस

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

पश्चिम रेलवे ने 5 नवंबर, 2024 को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। अपनी विनम्र शुरुआत के बाद से रेलवे ने राष्ट्र की सेवा में अपने 70 वर्षों से अधिक की यात्रा में कई मील के पथर हासिल किए हैं। 74वें स्थापना दिवस के पूर्व संस्था पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने पश्चिम रेलवे के मुख्यालय भवन के प्रबंधक ने अधिकारियों को सूचित किया कि एक अतिथि अपने कमरे में बेहोश पाया गया है।



1855 को कंपनी ने सूरत से बड़ौदा और अहमदाबाद तक रेलवे लाइन बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता किया। गुजरात में उगाए जाने वाले कपास की पश्चिमी बंदरगाह तक भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तर (सूरत के उत्तर में) से बॉम्बे तक एक लाइन शुरू करने के लिए एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अगले वर्ष लाइन पर काम शुरू हुआ और बॉम्बे में उत्तर-दक्षिण रेलवे लाइन शुरू करने की शुरुआत की नींव रखी गई। अपने वर्तमान स्वरूप में पश्चिम रेलवे 5 नवंबर, 1951 को अपने पूर्ववर्ती, तत्कालीन बॉम्बे, बरोडा एंड सेंट्रल इंडिया (BB&CI) रेलवे के 1855 में शामिल किया गया था, जिसकी शुरुआत पश्चिमी थट पर गुजरात राज्य के अंकलेश्वर से उज्जैन तक 29 मील की ब्रॉड गेज ट्रेक के निर्माण के साथ हुई थी और तब इसका मुख्यालय सूरत था। बाद में उसी वर्ष 21 नवंबर

के साथ विलय से अस्तित्व में आई। पश्चिम रेलवे का वर्तमान अधिकार क्षेत्र 6 मंडलों अर्थात् मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और रतलाम मंडल में है। 3 मार्च, 1961 को पश्चिम रेलवे द्वारा शहरी इलाकों में यात्रियों की बढ़ती मांग के कारण 9 कोच वाली उपनगरीय ट्रेनें शुरू की गईं। 1972 में, पश्चिम रेलवे ने अप नी प्रतिष्ठित मुंबई-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की, जो भारतीय रेल नेटवर्क पर सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम लाइनों में से एक है। दुनिया की पहली महिला स्पेशल ट्रेन, पहली 15-डिब्बों वाली उपनगरीय ट्रेन और भारत में पूरी तरह से वातानुकूलित पहली उपनगरीय ट्रेन की शुरुआत से लेकर एक के बाद एक मील के पथर स्थापित करने की अपनी यात्रा जारी रखते हुए, इसने परिचालन, सुरक्षा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाते जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रथम स्थान अर्जित किए हैं। पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए चंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी चला रहा है और हाल ही में पुज और अहमदाबाद के बीच नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत की गई है।

भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेटी ने महाराष्ट्र चुनाव से नामांकन लिया वापस

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी तारीख खत्म हो गई है। जहां राजनीतिक दल से बगावत कर निर्दलीय नामांकन अर्ज दाखिल करने वाले नेता नामांकन वापस ले लिए हैं। इस बीच गोपाल शेटी ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता



पूर्व भाजपा सांसद गोपाल शेटी ने बोरोवली सीट से उम्मीदवारी

न मिलने पर नाराजगी जाहिर की थी। जिसके बाद उन्होंने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था और बोरोवली सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन अर्ज दाखिल कर दिया था। उन्होंने बोरोवली सीट से भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार संजय उपाध्याय के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था।

मुख्तार शेख ने नामांकन लिया वापस

गोपाल शेटी से पहले सोमवार को करखा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के बागी नेता मुख्तार शेख ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। मुख्तार शेख ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था। मुख्तार शेख ने अपना नामांकन वापस लेने और एमवीए के आधिकारिक उम्मीदवार रवींद्र धोंकर का समर्थन करने का फैसला किया है।

गोपाल शेटी ने झोपड़पट्टी को लेकर उठाया था मुद्दा

गोपाल शेटी कहते हैं, 'कभी कोई मतभेद नहीं था। एक खास मुद्दे से जुड़ी बातें थीं, मुझे लगता है कि यह सही जगह पर पहुंच गया है। क्या हुआ और कैसे हुआ, यह कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पार्टी सर्वोच्च है, व्यक्ति छोटे हैं।'

देवेंद्र फडणवीस ने गोपाल शेटी को मनाया



बता दें, कि शनिवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेटी से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गोपाल शेटी से चुनाव से निर्दलीय नामांकन वापस लेने के लिए कहा था। इसके बाद गोपाल शेटी ने भी देवेंद्र फडणवीस को भरोसा दिलाया था कि वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो। लेकिन नामांकन वापस नहीं लिया था और आज नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन गोपाल शेटी ने बोरोवली विधानसभा क्षेत्र की सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग को लगाई फटकार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों फ्रांसिस न्यूटन सूजा और अकबर पद्मसी की सात पेंटिंग्स को को जब्त करने को लेकर सीमा शुल्क विभाग को फटकार लगाई है। अदालत ने उसे जब्त पेंटिंग्स को रिलीज करने का आदेश दिया है। सीमा शुल्क विभाग ने नमन पेंटिंग को अश्लील होने का दावा करते हुए जब्त किया था। न्यायमूर्ति एम.एस.सोनकर और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की पीठ के समक्ष लंदन में नीलामी में अकबर पद्मसी के तीन और एफएन सूजा के चार पेंटिंग खरीदे वाली कंपनी बी.के.पोलीमेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को और सोमेश श्रेयस श्रीवास्तव और सौरभ श्रेयस श्रीवास्तव की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सीमा शुल्क



विभाग की ओर से वकील जितेंद्र मिश्रा और वकील अभिषेक मिश्रा पेश हुए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी बिना उचित औचित्य के यह निर्धारित करने के लिए सामुदायिक मानकों का प्रतिनिधित्व करने का मनमाना ढंग से दावा नहीं कर सकते कि क्या अश्लील है? पीठ ने एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो कमिश्नरेंट के सीमा शुल्क विभाग के सहायक आयुक्त के 1 जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत पेंटिंग्स जब्त की गई थीं।

सार्वजनिक अधिसूचना

माहिम स्टेशन के माहिम साउथ फुट ओवर ब्रिज को बंद कराना
माहिम साउथ मुंबई महानगरपालिका फुट ओवर ब्रिज हावर्ड लाइन पर डेक स्लैब के पुनर्निर्माण के लिए तोड़ा जाना आवश्यक है. इसलिए, यह दिनांक 10.11.2024 से 30.11.2024 तक बंद रहेगा. यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए बहुत खेद है।
पश्चिम रेलवे
www.indianrailways.gov.in

पश्चिम रेलवे

पश्चिम रेलवे
रखरखाव कार्य
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II, पश्चिम रेलवे, रतलाम (म.प्र.) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किया है. ई-निविदा संख्या: आरटी एम/एनआरडी/बीबीडीसीई (सीआर) II/9. कार्य का नाम: निर्माण इकाई - रतलाम के आवस्यीय स्टेशन क्वार्टर, कार्यालय और अधिकारी विश्राम गृह की मरम्मत - रखरखाव तथा पश्चिम रेलवे की नीचम - रतलाम दोहरीकरण परियोजना के संबंध में विद्युत कार्य सहित रतलाम में एस एंड टी गोदाम, एस एंड टी कार्यालय का निर्माण, एनआईटी लागत: 43783363.61/-, बोलो सुरक्षा: 369000/-, बोलो जमा करने की अंतिम तिथि: 22.11.2024, 15:00 बजे तक. बोलो खोलने की तिथि: 22.11.2024 को 15:30 बजे. अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.irops.gov.in पर जाएं।
लाक कर: facebook.com/WesternRly

न्यूज़ ग्रीफ

संपत्ति के पुनर्वितरण पर संविधान पीठ आज सुनाएगी अपना फैसला

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ मंगलवार को इस कानूनी सवाल पर अपना सुनाएगी कि क्या सरकार के पास निजी संपत्ति अधिग्रहित कर उनका पुनर्वितरण करने का अधिकार है या नहीं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ की अगुवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। संविधान पीठ ने 1 मई को सभी पक्षों को सुनने के बाद इस संवैधानिक सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था कि 'क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39बी के तहत सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? यह इस मामले में जितना संवैधानिक सवाल जुड़ा है, उतना ही, राजनीतिक सवाल भी जुड़ा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के चल रही राजनीतिक बहस के फैसला सुरक्षित रखते हुए संविधान पीठ ने एक उदाहरण देते हुए सवाल किया था कि 'क्या भारत के बाहर के सेमीकंडक्टर चिप निर्माता को देश में एक कंपनी स्थापित करने के लिए कहा जाए, लेकिन बाद में उससे कहा जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में दो दशक से भी अधिक समय से यह मामला लंबित था।

दिल्ली मेयर चुनाव की तारीख का ऐलान, 14 नवंबर को सदन की बैठक

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के महापौर और उपमहापौर चुनाव 14 नवंबर को सदन की बैठक में होने। इस वर्ष अनुसूचित जाति (एससी) से महापौर पद आरक्षित है। इस वर्ष अप्रैल में महापौर का चुनाव निर्धारित किया गया था लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण निगम ने महापौर व उपमहापौर चुनाव को टाल दिया था। इससे पूर्व 28 अक्टूबर को निगम की सदन की बैठक में विपक्ष ने महापौर के चुनाव कराने के लिए विरोध जताया था। तब महापौर डॉ शैली ओबरोय ने हंगामे के दौरान सदन की कार्यवाही को अगली तारीख तक स्थगित कर दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि नवंबर में महापौर पद के चुनाव होंगे। इस चुनाव में निगम के सभी पार्षद, दिल्ली विधानसभा स्पीकर की तरफ से मनोनीत किए गए 14 विधायक, दिल्ली के सात लोकसभा सांसद और तीन राज्यसभा सांसद चुनाव में वोट डालेंगे।

2000 रुपये के 98 प्रतिशत नोट वापस आए

मुंबई। आरबीआई ने सोमवार को कहा कि 2000 रुपये के 98.04 प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और केवल 6,970 करोड़ रुपये के ऐसे नोट जनता के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने कहा कि 19 मई, 2023 को कारोबार बंद होने पर कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के बैंक नोट प्रचलन में थे। प्रचलन में शामिल नोटों का मूल्य 31 अक्टूबर, 2024 को कारोबार बंद होने पर 6,970 करोड़ रुपये रह गया था।

ज्वालामुखी विस्फोट से कई मकान जलकर खाक

मौमेरे। इंडोनेशिया के प्तोरेस द्वीप में ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण छह लोगों की मौत हो गई है। इंडोनेशिया की आवाद प्रबंधन एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

कोलकाता रेप-मर्डर केस: 87 दिन बाद आरोप तय

एजेंसी | कोलकाता

पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। 11 नवंबर से मुकदमे की रोजना सुनवाई होगी। सोमवार को पेशी के बाद पुलिस जब संजय को बाहर लेकर निकली तो पहली बार वह कैमरे पर कहता नजर आया कि ममता सरकार उसे फंसा रही है।



रॉय के दावे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए: अधीर चौधरी

कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के वरिष्ठ नेता अधीर चौधरी ने कहा कि रॉय के दावे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, 'आरोपी के ऐसे दावों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। हम कहते रहे हैं कि ऐसा अपराध किसी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। यह सामूहिक अपराध है। हमें नहीं पता है कि सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच कोई गुप्त गठजोड़ है या नहीं। हमें संदेह है।' कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि पुलिस की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। पिछले महीने पेश प्रारंभिक आरोप पत्र में सीबीआई ने रॉय को मामले में 'एकमात्र मुख्य आरोपी' बताया था। इस बीच, आर जी कर अस्पताल में ही भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई के दौरान इस सीबीआई ने अलीपुर की विशेष अदालत को बताया कि अपराध के पीछे 'गहरी साजिश' है।



'सीबीआई जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करे'

कोलकाता उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने का आदेश दिया था। इस मामले में घोष को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, नागरिक समाज संगठनों ने करुणामयी क्रॉसिंग से साट्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय तक रैली निकाली और मांग की कि एजेंसी आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले की जांच में तेजी लाए। इस मार्च में हिस्सा लेने वाली स्कूल अध्यापिका लिपिका चक्रवर्ती ने कहा, 'घटना को लगभग तीन महीने हो चुके हैं। सीबीआई क्या कर रही है? उसकी जांच में कोई स्पष्टता नहीं है। हम चाहते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करे।'

6 नवंबर को सुखबीर बादल पर फैसला, श्री अकाल तख्त सुनाएगी धार्मिक सजा

एजेंसी | नई दिल्ली

शिमोगी अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के राजनीतिक भविष्य का फैसला 6 नवंबर को होगा। श्री अकाल तख्त ने सिख विद्वानों और बुद्धिजीवियों की 6 नवंबर को बैठक बुलाई है। श्री अकाल तख्त सचिवालय में होने वाली इस बैठक में सुखबीर बादल के तनखईया मामले और धार्मिक सजा को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा। जत्थेदार ज्ञानी रघवीर सिंह द्वारा बुलाई गई बैठक में 18 सिख विद्वान और बुद्धिजीवी हिस्सा लेंगे।

इस वजह से तनखईया घोषित किया गया सुखबीर बादल को

वर्ष 1801 में सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह भी तनखईया घोषित किए जा चुके हैं। उनके अलावा पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला भी तनखईया घोषित होने के बाद धार्मिक सजा का भुगतान कर चुके हैं। सजा में भले ही कोई शारीरिक तकलीफ या जेल जैसी सजा शामिल नहीं होती परंतु पंजाब के मतदाताओं पर धार्मिक सामाजिक बहिष्कार के असर के तौर पर जरूर देखा जाता है। सुखबीर बादल पर दस सालों की सरकार के दौरान डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम के प्रति नरम रुख अपनाए जाने, पोशाक मामले, वर्ष 2012 में सुमेध सेनी को पंजाब पुलिस महानिदेशक बनाने के मामले, बरगाड़ी कांड में सिख युवाओं की हत्या और पीड़ितों के न्याय में ढील जैसे आरोपों पर तनखईया घोषित किया गया है।



क्या है मामला ?

शिमोगी अकाली दल से नाराज बागी अकाली नेताओं ने सर्वोच्च सिख धार्मिक पीठ श्री अकाल तख्त साहिब को शिकायत दी थी कि अकाली सरकार के दौरान पंजाब में वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2017 के दौरान धर्म से संबंधित कई गलतियों की गई थी जो सिखों के हित में नहीं थी। इसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने 30 अगस्त को सुखबीर बादल को तनखईया घोषित किया था। उसके बाद से लेकर अब तक सिख धर्मगुरुओं ने सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा नहीं सुनाई है। सुखबीर के तनखईया होने की वजह से श्री अकाल तख्त ने सुखबीर को विधानसभा उपचुनावों में हिस्सा लेने या प्रचार करने की छूट भी नहीं प्रदान की थी। इसकी वजह से शिमोगी अकाली दल ने विधानसभा उपचुनावों का मैदान भी छोड़ दिया था।

बेअंत हत्याकांड के दोषी की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को अल्टीमेटम याचिका पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या मामले में फांसी की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना की अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है। याचिका में राजोआना ने दया याचिका पर फैसला लेने में देरी के आधार पर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदले जाने और रिहाई की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि दया याचिका पर जो भी फैसला लेना है वह लें या फिर हम राजोआना की अर्जी पर विचार करेंगे।



रोहतगी ने कहा कि राजोआना पिछले 29 साल से जेल में बंद है। उन्होंने अंतरिम रिलीफ की मांग करते हुए कहा कि जब तक राष्ट्रपति दया याचिका पर फैसला लेते हैं तब तक राजोआना को रिहा किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को जारी किया था नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल के राजोआना की अर्जी पर 27 सितंबर को नोटिस जारी कर केंद्र और राज्य से जवाब दायित्व करने को कहा था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद-32 के तहत अर्जी दायित्व कर कहा है कि उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदली जाए और यह भी दलील दी गई कि रिहाई की जाए। साथ ही कहा कि दया याचिका पर फैसला लेने में काफ़ी देरी हुई है। दया याचिका राष्ट्रपति के सामने 1 साल 4 महीने पेंडिंग है। याचिका की ओर से मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि मर्जी पिटिशन पर फैसला लेने में काफ़ी देरी हुई और यह स्तब्धकारी है।

धोखाधड़ी रोकने को हर मैसेज पर रहेगी नजर

जांच में जुटी वन टीम, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है 13 हाथियों का झुंड

एजेंसी | नई दिल्ली

ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं साइबर अपराध को रोकने की दिशा में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा लगातार सख्तों की जा रही है। इसी कड़ी में संदेश की ट्रेसिबिलिटी यानी निगरानी करने का फैसला लिया है, जिसके तहत वाणिज्यिक यानी टेलीमार्केटिंग संदेश को भेजने वाले से लेकर अंतिम रूप से मैसेज प्राप्त करने वाले व्यक्ति एवं संस्था तक को ट्रैक किया जा सकेगा। पहले इस व्यवस्था को एक नवंबर से लागू किया जाना था लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है लेकिन इस बीच प्रतिदिन के हिसाब से चेतावनी जारी करने का फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत संदेश से जुड़ी सारी प्रक्रिया को ट्रैक किया जाएगा। इसमें प्रिंसिपल एंटीटी यानी भेजे जा रहे संदेश में शामिल शब्दों की कुंजी और टेलीमार्केटर्स श्रृंखला को परिभाषित करना शामिल है जिसके माध्यम से



संदेश के टेलीकॉम ऑपरेटर तक की पहचान हो सकेगी। ट्राई के निर्देश पर 30 नवंबर 2024 तक दैनिक आधार पर टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा ऐसे संदेशों को लेकर चेतावनी जारी की जाएगी, जिनका पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है और सँदिग्ध मैसेज हैं। उसके बाद एक दिवस से ऐसे संदेश को खारिज कर दिया जाएगा, जिनकी श्रृंखला परिभाषित नहीं है। श्रृंखला परिभाषित होने से आशय यह है कि टेलीमार्केटिंग कंपनी को मैसेज भेजने से पहले यह बताना होगा कि वो किस तरह का मैसेज उपभोक्ताओं को भेज रहा है और कितने उपभोक्ताओं को भेजा जाएगा। इससे सबसे बड़ी मदद यह मिलेगी कि अगर कोई संदेश या लिंक धोखाधड़ी के उद्देश्य से यूजर्स को भेजा जाता है तो उससे भेजने वाले से लेकर कितनी व्यक्तियों को भेजा गया है, उसका एक डेटाके में पता लगाया जा सकेगा। यह सारी प्रक्रिया मोबाइल यूजर्स को फिशिंग लिंक मैसेज से बचाने के लिए अपनाई जा रही है।

ऑपरेटर्स ने मांगा था अतिरिक्त समय

बीते दिनों टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ट्राई के सामने अपना पक्ष रखा था। उनका कहना था कि ट्रेसिबिलिटी नियमों का पालन न करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। मैसेज को ब्लॉक करने से यूजर्स काफ़ी परेशान भी होंगे। ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम होने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय चाहिए क्योंकि नया नियम बैंक द्वारा भेजे जाने वाले ओटीपी, टेलीमार्केटिंग कंपनियों और कारोबार से जुड़ी अन्य कंपनियों एवं संस्थाओं पर भी लागू होगा। किसी वजह से सही मैसेज भी ब्लॉक किए जाते हैं तो उससे लोगों को ओटीपी के जरिए ऑनलाइन लेन-देन में दिक्कत आ सकती है।

ट्राई की अब तक की कार्रवाई

- अगस्त में स्पैम कॉल के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी किए
- 800 से अधिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों को ब्लैक लिस्ट किया
- 18 लाख मोबाइल नंबर व दूरसंचार संसाधनों को डिस्कनेक्ट किया

कनाडा से तनाव के बीच पहली बार बोले पीएम मोदी

'मंदिर पर हमला कारगराना, ऐसे कृत्य डिगा नहीं सकते'

एजेंसी | नई दिल्ली

कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा की गई हिंसा और हिंदुओं के साथ मारपीट प्रकरण पर अब पीएम नरेंद्र मोदी का बयान आया है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव पर पीएम मोदी पहली बार बोले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि वो इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे कृत्य भारत के संकल्पों को कभी कमजोर नहीं करेंगे। रविवार को खालिस्तानी झंडे लिए प्रदर्शनकारियों की कनाडा के ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में लोगों के साथ झड़प हो गई। आरोप है कि खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं के साथ मारपीट भी की। जिसके बाद ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने एक कड़ा बयान जारी कर 'भारत विरोधी' तत्वों द्वारा किए गए हमले की निंदा की। हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का भी बयान आया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानी उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कनाडा सरकार से मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।



कनाडा से तनाव के बीच पहली बार बोले पीएम मोदी

कनाडा से राजनयिक विवाद और अब हिंदू मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा उत्पात मचाने के बाद यह पहली बार है जब पीएम मोदी का बयान आया है। पीएम मोदी ने हमले को लेकर कहा, 'मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे राजनयिकों को डराने-धमकाने की कारगरानापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी।'

मारपीट और चले लात-घूंसे

केनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन' की रिपोर्ट के अनुसार, पील क्षेत्रीय पुलिस ने रविवार को बताया कि ब्रैम्पटन के एक मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ था और सोशल मीडिया पर प्रसारित घटना के कुछ अप्रुष्ट वीडियो में प्रदर्शनकारी खालिस्तान के समर्थन में बैनर पकड़े नजर आए। रिपोर्ट में कहा गया कि वीडियो में लोग एक-दूसरे पर घूंसे बरसाते और एक-दूसरे पर डंडों से हमला करते नजर आए। यह घटना हिंदू सभा मंदिर के आसपास के मैदान में होती प्रतीत हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा यूपी मद्रसा एक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित कर चुका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को यूपी मद्रसा कानून को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। 5 अप्रैल 2024 को 'UP बोर्ड ऑफ मद्रसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही केंद्र और UP सरकार से जवाब भी मांगा था।



क्या है मामला ?

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मद्रसों का नियमन को राष्ट्रीय हित में बताते हुए कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग-थलग जगह बनाकर देश की सैकड़ों साल पुरानी मिली-जुली संस्कृति को खत्म नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने कहा था कि देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अविभाज्य नहीं रही है। पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश मद्रसा अधिनियम 2004 को खत्म किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका अनुजम कादरी एवं अन्य की अपीलों पर फैसला सुरक्षित रखा था। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा था कि 'धर्मनिरपेक्षता का मतलब है- जियो और जीने दो।'

खबर संक्षेप

नवंबर में तापमान सामान्य से अधिक, ठंड में देरी

लखनऊ: नवंबर की शुरुआत में भी ठंड का असर नहीं दिख रहा है। इस समय अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से क्रमशः 2.4 और 2 डिग्री अधिक चल रहे हैं। रविवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग का कहना है कि ला नीना के सक्रिय न होने से ठंडी हवाओं का प्रभाव कम है, हालांकि इसके सक्रिय होने में अभी एक सप्ताह और लग सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के चक्र में बदलाव आया है, जिससे ठंड अब दिसंबर में शुरू होने की संभावना है। शनिवार को कानपुर में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जिसमें न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री रहा, जबकि दिन का तापमान 35.8 डिग्री पर पहुंच गया।

लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों की

अनिश्चितकालीन हड़ताल
गाजियाबाद: गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदेश के सभी जिलों के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिला बार एसोसिएशन ने मुख्य गेट को धरना स्थल बना लिया है, और कोर्ट के सभी गेट बंद कर दिए हैं। वकीलों ने जिला जज कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर के मामले में विवाद के बाद हुई इस कार्रवाई के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। हड़ताल के दौरान वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

बिहार में भी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी



पटना: उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब अजर्बोनाथ धाम रखा जाएगा। इस प्रस्ताव को नगर परिषद ने राज्य सरकार को भेजा है, जिसे बिहार सरकार जल्द ही रेलवे मंत्रालय को भेजेगी। स्थानीय लोगों, पंडा समाज और जूना अखाड़ा समिति ने लंबे समय से स्टेशन का नाम बदलने की मांग की थी। यह पहला मौका नहीं है जब देश में रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है; इससे पहले उत्तर प्रदेश में मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया था।

शिक्षकों के तबादले की अवधि 5 साल से घटकर 3 साल हुई

27 अहम प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी

एजेंसी | लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य के विकास के लिए नई नीतियों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे शिक्षा, पशुपालन, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण में सुधार की संभावना बढ़ी है। विभिन्न क्षेत्रों में उदाए गए कदमों से न केवल विकास की गति बढ़ेगी, बल्कि लोगों की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है, जिससे उच्च शिक्षा में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी और छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र की स्थापना

जनपद बागपत में एक अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स में संशोधन

उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1971 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिल सकेगा।

उच्च शिक्षा में तबादला नीति में संशोधन

उच्च शिक्षा विभाग में अध्यापकों के तबादलों से संबंधित नीति का प्रस्ताव पास किया गया है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1971 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिल सकेगा।

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का अनुरक्षण कार्य

अमरा से लखनऊ तक 302 किलोमीटर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के अगले 5 वर्षों तक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य की स्वीकृति दी गई है।

लखनऊ में विदेशी भाषाओं के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय

लखनऊ में इंग्लिश और विदेशी भाषाओं के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त कर चुका है। यह छात्रों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा।

27 हजार स्कूल बंद करने की खबर पर सरकार का खंडन

बेसिक शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने कहा- खबरें भ्रामक, कोई स्कूल बंद नहीं होगा



एजेंसी | लखनऊ

उत्तर प्रदेश में 27 हजार से अधिक प्राथमिक और जूनियर स्कूलों को बंद करने की खबरों का बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त खंडन किया है। विभाग की महानिदेशक कंचन वर्मा ने कहा कि मीडिया में चल रही इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और यह पूरी तरह भ्रामक और आधारहीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी भी स्कूल को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग प्रदेश में विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और ड्रापआउट दर को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस कथित निर्णय पर सरकार की आलोचना करते हुए इसे गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50 से कम छात्रों वाले लगभग 27,764 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करना सही नहीं है। उनका मानना है कि यह निर्णय उन बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देगा जो पहले से ही कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। मायावती ने सुझाव दिया कि सरकार को इन स्कूलों का अन्य

विद्यालयों में विलय करने के बजाय उन्हें सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा के अच्छे अवसर मिल सकें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बसपा अध्यक्ष मायावती दोनों ने इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने इसे शिक्षा और वंचित तबकों के बच्चों के भविष्य के खिलाफ बताया है। सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया था ताकि हर बच्चे के लिए एक किलोमीटर की दूरी पर स्कूल उपलब्ध हो। प्रियंका ने कहा कि भाजपा सरकार के इस कदम से कमजोर तबकों के बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ होना कठिन हो जाएगा। उन्होंने इसे जनविरोधी नीति करार दिया। कंचन वर्मा ने अपने बयान में कहा कि सरकार स्कूलों को बंद करने के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों की उपलब्धता और ड्रापआउट दर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विभाग समय-समय पर अध्ययन और मूल्यांकन करता रहता है ताकि शिक्षा को अधिक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके।

भ्रष्टाचार, पेपर लीक, परिवारवाद और झूठे वादों पर पीएम मोदी ने सोरेन सरकार को घेरा

एजेंसी | गढ़वा

झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूबी हुई है।



युवाओं का भविष्य

उन्होंने झारखंड के युवाओं की प्रतिभा और पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। पीएम ने आरोप लगाया कि जेएमएम और कांग्रेस सरकार बनने के बाद सरकारी पदों को

युवाओं के साथ धोखा किया है।

नवजात बच्ची को जिंदा दफनाने का मामला

मन्त्रीखेड़ा गांव में दिल दहला देने वाली घटना

एजेंसी | मुरादाबाद

नखासा थाना क्षेत्र के मन्त्रीखेड़ा गांव में एक हृदय विदारक घटना प्रकाश में आई है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात बेटी को सरसों के खेत में जिंदा दफना दिया। यह घटना उस समय सामने आई जब बच्ची के रोने की आवाज पास में खेल रहे बच्चों ने सुन ली। गनीमत यह रही कि बच्ची के चेहरे का कुछ हिस्सा जमीन से बाहर था, जिससे वह सांस ले पा रही थी। जब बच्चों ने उसकी आवाज



सुनी, तो उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्ची को निकालकर नखासा थाना पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शुरु की जांच

पुलिस ने बच्ची को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर रही है। स्थानीय निवासी इस घटना को लेकर गुस्से में हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं समाज में घृणा और नफरत का संकेत देती हैं, जिससे यह साफ है कि हमें अपने समाज में मानवीयता और सहानुभूति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

रिलायंस जिओ का IPO 2025 में, रिटेल का IPO बाद में

2025 में आएगा जिओ का IPO

एजेंसी | नई दिल्ली

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 में अपने टेलीकॉम बिजनेस, जिओ, का IPO लाने की तैयारी में है। विश्लेषकों का अनुमान है कि जिओ का मूल्यांकन \$100 बिलियन से अधिक हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी भारत का सबसे बड़ा IPO पेश करना चाहती है, जो मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ सके।



जिसमें ई-कॉमर्स और विभिन्न रिटेल फॉर्मेट्स में निवेश शामिल है। कंपनी ने जिमी चू, माक्स एंड स्पेंसर और प्रेट एंज जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ साझेदारी की है और हैमिलीज का स्वामित्व भी रखती है। सूत्रों के अनुसार, रिलायंस ने एक ही समय में दो बड़े IPO लाने से बचने का निर्णय लिया है। जिओ का IPO 2025 में आएगा, जबकि रिटेल का IPO उसके बाद आएगा ताकि निवेशकों पर दबाव न बढ़े और बाजार स्थिर रहे। जिओ प्लेटफॉर्म में 33% और रिलायंस रिटेल में 12% हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों की है, जिससे हाल के वर्षों में इन दोनों कारोबारों ने कुल \$25 बिलियन का निवेश जुटाया है।

रिटेल IPO के लिए इंतजार

रिलायंस का रिटेल IPO 2025 के बाद लॉन्च होने की संभावना है। कंपनी आंतरिक संचालन से जुड़े कुछ मुद्दों को हल करना चाहती है, ताकि IPO से पहले यह क्षेत्र मजबूती से खड़ा हो सके। रिलायंस रिटेल का भारत में 3,000 से अधिक सुपरमार्केट का नेटवर्क है और कंपनी अब क्विक कॉमर्स में भी कदम बढ़ा रही है। रिलायंस जिओ भारत में एलोन मस्क की स्टारलिन सेवा से मुकाबले की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने NVIDIA के साथ साझेदारी की है ताकि भारत में आई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। जिओ को गूगल और मेटा जैसे डिजिटल का भी समर्थन प्राप्त है। रिलायंस रिटेल तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसमें 3015 रूपए पर पहुंचे, जो 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर है। मात्र 10 दिनों में शेयरों में 100% से अधिक का उछाल आया है, जिससे निवेशकों की पूंजी दोगुनी हो गई है। कंपनी का मार्केट कैप अब 85,700 करोड़ रूपए के पार हो गया है। वारी एनर्जी का IPO 21 से 23 अक्टूबर 2024 के बीच खुला था,

Niva Bupa Health Insurance का IPO 7 नवंबर से

IPO का प्राइस बैंड और रकम जुटाने की योजना

एजेंसी | नई दिल्ली

हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी Niva Bupa अपने IPO के माध्यम से पब्लिक में शामिल होने जा रही है। इसके लिए प्रति शेयर प्राइस बैंड 70-74 रूपएतय किया गया है। कंपनी का लक्ष्य 2,200 करोड़ रूपएजुटाने का है, जिसमें 800 करोड़ रूपएका नया निगम और 1,400 करोड़ रूपएका बिक्री पेशकश शामिल है। Niva Bupa का IPO 7 नवंबर को सबक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 11 नवंबर को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए यह इश्यू 6 नवंबर को ही खुल जाएगा। इस बिक्री पेशकश में प्रमोटर् बूपा सिंगापुर होल्डिंग्स और टू



नॉर्थ 350 करोड़ और 1,050 करोड़ के शेयर ऑफर-फॉर-सेल के तहत बेचेगा। IPO के सबक्रिप्शन बंद होने के बाद, 12 नवंबर को शेयर आवंटन फाइनल होगा और 13 नवंबर को आवंटितों के डीमैट खातों में शेयर जमा किए जाएंगे। कंपनी के शेयर 14 नवंबर को BSE और NSE पर लिस्ट होने की संभावना है। मुख्यम स्थित Niva Bupa Health Insurance 800 करोड़ रूपएका

उपयोग अपनी पूंजी को मजबूत करने और सॉल्वेंसी स्तर बनाए रखने के लिए करेगी। इस IPO के ब्रुक रनिंग लीड मैनेजर ICICI सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टेनली इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, HDFC बैंक और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं। KFin Technologies इस ऑफर के रजिस्ट्रार हैं। वित्त वर्ष 2024 में, Niva Bupa Health Insurance ने 81.85 करोड़ रूपएका शुद्ध लाभ कमाया, जो पिछले वर्ष के 12.5 करोड़ रूपएसे अधिक है। हालांकि, ऑपरिंग लाभ 350.9 करोड़ से घटकर 188 करोड़ रह गया।

वारी एनर्जी के शेयरों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी

10 दिन में निवेशकों का पैसा दोगुना

एजेंसी | नई दिल्ली

बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सोलर कंपनी वारी एनर्जी (Waaree Engergies) के शेयरों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। सोमवार को BSE पर कंपनी के शेयर 4% से अधिक की तेजी के साथ 3015 रूपए पर पहुंचे, जो 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर है। मात्र 10 दिनों में शेयरों में 100% से अधिक का उछाल आया है, जिससे निवेशकों की पूंजी दोगुनी हो गई है। कंपनी का मार्केट कैप अब 85,700 करोड़ रूपए के पार हो गया है। वारी एनर्जी का IPO 21 से 23 अक्टूबर 2024 के बीच खुला था,

जिसमें शेयर का इश्यू प्राइस 1503 रूपए रखा गया था। 28 अक्टूबर को BSE पर लिस्टिंग के बाद शेयर 2550 रूपए पर खुले और पहले ही दिन 2336.80 रूपए पर बंद हुए। इसके बाद से ही शेयरों में तेजी जारी है, जिससे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है। वारी एनर्जीज का IPO कुल 79.44 गुना सबक्राइब हुआ था। रिटेल निवेशकों का कोटा 11.27 गुना भरा, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में 65.25 गुना और क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 215.03 गुना सबक्रिप्शन मिला। रिटेल निवेशकों के लिए एक लॉट 9 शेयरों का था, जिसकी कीमत 13,527 रूपए थी।

शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 79 हजार के नीचे

सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट

एजेंसी | नई दिल्ली

सोमवार, 4 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 941.88 अंक गिरकर 78,782.24 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 309.00 अंक लुढ़ककर 23,995.35 पर आ गया। सेंसेक्स 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई, जिसमें अजन्ती पोर्ट्स, रिलायंस, सनफार्मा और बजाज फिनसर्व प्रमुख रहे। वहीं, एमएंडएम, टेक महिंद्रा, एसबीआई और एचसीएल टेक ने बढ़त दर्ज की।

क्या हैं बाजार की गिरावट के कारण?



विशेषज्ञों के अनुसार, बाजार में गिरावट का एक बड़ा कारण भारतीय कंपनियों की दूसरी तिमाही की कमजोर आय रिपोर्ट रही। इसके साथ ही अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने भारी मात्रा में शेयरों की बिक्री की, जिससे नेगेटिव सैटीमेंट बना। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अस्थिरता और भारतीय रुपये की कमजोरी भी गिरावट के कारक बने।

रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर

सोमवार को भारतीय रुपया 84.12 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले यह 84.05 पर खुला था। रुपये की इस कमजोरी ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया। बाजार सौमवार सुबह ही गिरावट के साथ खुला था। सेंसेक्स 547.94 अंक की गिरावट के

साथ 79,176.18 पर खुला, जबकि निफ्टी 168.50 अंक गिरकर 24,135.80 पर शुरू हुआ। पी-ओपीएम सत्र में बाजार ने स्थिरता दिखाई, जिसमें सेंसेक्स 33.35 अंक गिरकर 79,690.77 और निफ्टी 11.50 अंक गिरकर 24,292.80 पर कारोबार कर रहे थे।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 5% उछाल, SUV बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

एजेंसी | नई दिल्ली

महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के शेयरों में 4 नवंबर को 5% की तेजी दर्ज की गई, जिससे स्टॉक बीएसई पर 2873.25 रूपए के स्तर पर बंद हुआ। SUV की बिक्री में 25% सालाना वृद्धि के कारण इस तेजी का रूझान देखा गया। इस उछाल के बाद कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 3.57 लाख करोड़ रूपए हो गया है। अक्टूबर में M&M



ने 54,504 SUV की बिक्री की, जो कंपनी का अब तक का सबसे उच्च मासिक आंकड़ा है। ऑटो और ट्रैक्टर सेगमेंट ने मिलकर कुल 96,648 वाहनों की बिक्री की। घरेलू कमर्शियल व्हीकल की बिक्री

28,812 यूनिट रही, जबकि ट्रैक्टर की बिक्री 65,453 यूनिट तक पहुंच गई, जो सालाना 30% की बढ़त है। महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के प्रेसिडेंट वीजय नाकरा ने कहा कि त्योहारी सीजन में सकारात्मक माहौल के चलते Thar ROXX को पहले 60 मिनट में 1.7 लाख बुकिंग प्राप्त हुई। इससे SUV पोर्टफोलियो में और मजबूती आई है। ट्रैक्टर सेगमेंट की घरेलू बिक्री 64,326 यूनिट तक पहुंच गई।

भारतीय महिला टीम करेगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी



एजेंसी | दुबई

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के सोमवार को जारी 2025 से 2029 तक के भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) के मुताबिक भारतीय महिला टीम घरेलू सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मेजबानी करेगी। इन दोनों बड़ी टीमों के अलावा भारत इस दौरान बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की टीमों की भी मेजबानी करेगा। जिम्बाब्वे हाल ही में एफटीपी में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। मई 2025 से अप्रैल 2029 तक चलने वाले इस एफटीपी में 400 से अधिक मैच खेले जाएंगे। इसमें वनडे की 44 सीरीज में 132 मैचों का जिक्र है। इसके साथ ही 2027 में छह टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी को भी इस एफटीपी में जगह दी गई है। इसके अलावा हर साल एक आईसीसी इवेंट भी होगा।

महिला एफटीपी

► टीम चार साल में न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेगी

चार सीरीज

भारत की महिला टीम इन चार वर्षों में न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा करेगी। एफटीपी में प्रत्येक सदस्य देश को अपने घरेलू मैदान और दूसरी टीम के घर में चार-चार सीरीज खेलनी हैं। भारतीय टीम इसके अलावा 2026 में महिला टी-20 विश्व कप से पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ त्रिकोणीय सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड महिला टी-20 विश्व कप की मेजबानी करेगा।

अधिक टेस्ट की मांग

आईसीसी के क्रिकेट महाप्रबंधक वसीम खान ने विज्ञापित में कहा, सदस्य देशों ने इस एफटीपी में अधिक टेस्ट मैच खेलने की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज सभी

बहु-प्रारूप सीरीज खेलने के लिए सहमत हैं, जिसमें वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय शामिल हैं। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया ऐसी अधिकतम सीरीज खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस दौरान इंग्लैंड, भारत और दक्षिण

अफ्रीका के खिलाफ दो-दो और वेस्टइंडीज के खिलाफ एक सीरीज खेलेगी। आईसीसी के सदस्यों ने आपसी सहमति से इस चक्र में त्रिकोणीय सीरीज को भी शामिल किया है।

रणजी का रण

शमी कर्नाटक और मप्र के खिलाफ नहीं खेलेंगे

एजेंसी | बेंगलुरु

मोहम्मद शमी की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी में अभी और देर होगी। इस अनुभवी तेज गेंदबाज को कर्नाटक और मध्य प्रदेश के खिलाफ होने वाले अगले दो दौर के रणजी ट्रॉफी मुकाबलों के लिए बंगाल की टीम में शामिल नहीं किया गया है। बंगाल बुधवार से यहां चिन्नास्वाममी स्टेडियम में कर्नाटक से भिड़ेगा जबकि 13 नवंबर से इंदौर में मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलेगा।



कुछ खिलाड़ियों की कमी खलेगी

शमी के अलावा बंगाल को सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन, विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल और तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की भी कमी खलेगी जो ऑस्ट्रेलिया में भारत ए टीम के साथ हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा रहे तेज गेंदबाज आकाश दीप को भी टीम में नहीं चुना गया। हालांकि मौजूदा घरेलू सत्र के बाद क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा को दो मैच के लिए चुना गया है।

फिटनेस का परीक्षण जरूरी

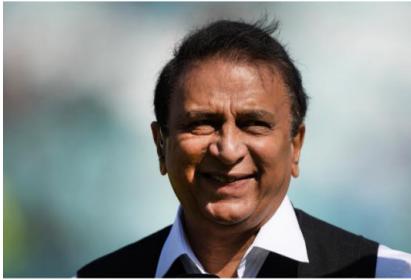
शमी से कर्नाटक के खिलाफ मैच में खेलने की उम्मीद थी जिससे वह वास्तविक मैच की स्थिति में फिटनेस का परीक्षण कर सकें। उन्होंने हाल में यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के टेस्ट मैच के बाद नेट पर पूरी ताकत से गेंदबाजी की थी, हालांकि इस दौरान उनके पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। उस दौरान भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल उन पर नजर रखे हुए थे। बाद में शमी ने एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान कहा कि वह नेट पर शत प्रतिशत फिट महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा था, मैं आधे रन अप से गेंदबाजी कर रहा था क्योंकि शरीर पर अधिक दबाव नहीं डाल सकता। इसलिए हमने फैसला किया कि मैं उचित तरीके से गेंदबाजी करूंगा और मैंने अपना शत प्रतिशत दिया। उम्मीद है कि मैं जल्द ही वापसी करूंगा।

टीम

अनुसूत मजूमदार (कप्तान), ऋद्धिमान साहा, सुदीप चर्जी, सुदीप परामी, शाहबाज अहमद, ऋतिक चर्जी, एविलिन घोष, शुवम डे, शाकिर हबीब गांधी, प्रदीप प्रमाणिक, आमिर गनी, इशान पोरेल, सूरज सिंघु, जायसवाल, मोहम्मद कैफ, रोहित कुमार और ऋषव विवेक।



अभ्यास मैच पर भारतीय टीम फिर विचार करे : गावस्कर



एजेंसी | नई दिल्ली

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले भारत और भारत ए टीम के बीच अभ्यास मैच को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। गावस्कर ने सोमवार को कहा, टेस्ट मैचों के बीच अंतराल में अभ्यास मैच होने चाहिए, भले ही यह वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन उन युवा खिलाड़ियों के लिए जरूरी है, जो पहले कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले हैं। उन्हें वहां की उछाल और पिचों से अभ्यस्त होने का मौका दिया जाना चाहिए।

'तेज गेंदबाजों का सामना करें'

गावस्कर ने कंगारू टुम के खिलाफ पहले बार खेलने जा रहे युवा खिलाड़ियों को धैर्य और खुद पर भरोसा रखने को कहा। उन्होंने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा समय ग्रींडउप और तेज गेंदबाजों का सामना करने की सलाह दी। भारतीय टीम को 10 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगा और उसे पर्थ में पहले टेस्ट से पूर्व भारत ए के खिलाफ एक आपसी मैच खेलना था। हालांकि अब अभ्यास मैच की जगह 'सेंटर-विकेट मैच' सिमुलेशन को तरजीह दी गई है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि इससे बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को अभ्यास मैच की तुलना में पिच पर अधिक समय बिताने का मौका मिल सकेगा।

ओल्मो के दो गोल से बार्सिलोना ने दर्ज की एक और जीत



एजेंसी | मैड्रिड

ला लिगा फुटबॉल चैंपियनशिप में 27 बार के चैंपियन बार्सिलोना का अभियान जारी है। उसने दानी ओल्मो के दो गोल की मदद से रविवार को एस्पेन्योल पर 3-1 से जीत दर्ज करके स्पेनिश फुटबॉल लीग के वर्तमान सत्र में अपना दबदबा बरकरार रखा। **बढ़त मजबूत की :** एक सप्ताह पहले सैंटियागो बर्नबेयू स्टेडियम में रियाल मैड्रिड को 4-0 से हराते वाले बार्सिलोना की तरफ से

राफिन्हा ने भी गोल 23वें मिनट में किया। इससे पहले ओल्मो ने 12वें मिनट में मैच का पहला गोल कर टीम का खाता खोला और फिर 31वें मिनट में अपना और टीम का दूसरा गोल किया। एस्पेन्योल का एकमात्र गोल जावी पुआडो ने 63वें मिनट में किया। बार्सिलोना अब मौजूदा चैंपियन रियाल मैड्रिड से नौ अंक आगे हो गया है, जिसका वेलेसिया में शानियार को होने वाला मैच बाढ़ के कारण स्थगित कर दिया गया था।

आईपीएल नीलामी नवंबर के अंत में रियाद में होगी

एजेंसी | नई दिल्ली



इंडियन प्रीमियर लीग की आगामी बड़ी नीलामी नवंबर के अंतिम हफ्ते में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्रों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, आईपीएल नीलामी रियाद में होगी और यह फ्रेंचाइजी को बता दिया गया है। संभावित तिथियां 24 और 25 नवंबर हैं। इस बार नीलामी बड़ी होगी जिसमें ऋषभ पंत, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर और अश्वीन सिंह जैसे भारत के स्टार खिलाड़ियों के लिए बोली लगेगी। दस फ्रेंचाइजी के पास 204 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 641.5 करोड़ रुपये की राशि है।

ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रदर्शन प्रभावित होगा : गिलक्रिस्ट, वार्नर

एजेंसी | सिडनी

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों एडम गिलक्रिस्ट और डेविड वार्नर को इसमें संदेह नहीं है कि न्यूजीलैंड से घर में करारी हार से भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता आहत हुई होगी। फिर भी उन्होंने कहा कि 22 नवंबर से पर्थ में शुरू हो रही पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा की टीम को आसानी से हराने के बारे में सोचना नासमझी होगी। गिलक्रिस्ट ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों पर अधिक असर होगा लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता कि उन्हें आसानी से हराया जा सकता है।

'बेबी जॉन' का टीजर जारी, वरुण धवन का दिखा धांसू अवतार

पिछले लंबे वक्त से वरुण धवन फिल्म 'बेबी जॉन' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी यह फिल्म इस साल की बहुचर्चित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान एटली ने संभाली है, जिन्होंने बीते साल शाहरुख खान के साथ फिल्म 'जवान' जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी। अब 'बेबी जॉन' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें वरुण का धांसू अवतार दिख रहा है। एक्शन से भरपूर इस टीजर को प्रशंसक पसंद कर रहे हैं।

25 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म

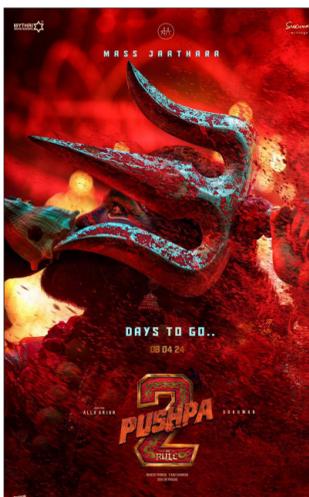
'बेबी जॉन' में वरुण की जोड़ी पहली बार अभिनेत्री वामिका गब्बी के साथ बनी है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश भी इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आएंगी। जैकी श्राफ भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। टीजर में तमाम सितारों की झलक दिख रही है। यह फिल्म इस साल क्रिसमस के खास मौके पर यानी 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है। यह एटली और वरुण के बीच पहला सहयोग है, जिसे लेकर प्रशंसक खूब उत्साहित हैं।



'पुष्पा: द रूल' में नजर आएंगी श्रीलीला

अल्लु अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा: द रूल' इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। यह 2021 में आई फिल्म 'पुष्पा: द राइज' का सीक्वल है, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुआ। 'पुष्पा: द रूल' 5 दिसंबर, 2024

को सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है। 'पुष्पा: द रूल' की स्टार कास्ट में शामिल हो गई हैं। वह फिल्म में अल्लु के साथ एक गाने में डांस करती नजर आएंगी। 'पुष्पा: द रूल' के आइटम नंबर के लिए श्रीलीला को चुना गया है।



श्रद्धा कपूर से हो चुकी है बातचीत

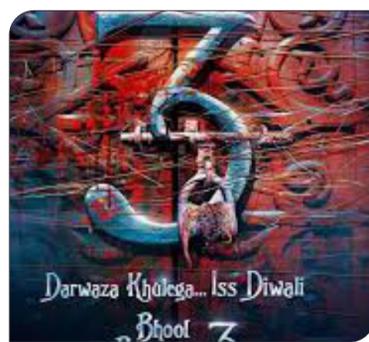
इससे पहले निर्माताओं ने श्रद्धा कपूर से भी संपर्क किया था, लेकिन मुंहमांगी रकम के कारण निर्माताओं ने उनकी छुट्टी कर दी। इसके अलावा इस आइटम नंबर के लिए तुपिन डिमरी से भी बात हो चुकी है। श्रीलीला फिल्म के एक विशेष गाने में डांस करती नजर आएंगी। इस दौरान अल्लु उनका साथ देने वाले हैं। 'पुष्पा: द रूल' के निर्देशन की कमान सुकुमार कर रहे हैं। पहले भाग का निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। फहद फासिल भी इस फिल्म में अपनी अदाकारी का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे।



'आजाद' से अमन देवगन की पहली झलक आई

अजय अपनी आगामी फिल्म 'आजाद' को लेकर चर्चा में हैं। अब इस फिल्म का पहला पोस्टर सामने आ गया है। इसके अलावा टीजर की रिलीज तारीख से भी पता चल गया है। 'आजाद' के जरिए रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। अजय के भांजे अमन देवगन भी इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। 'आजाद' से अमन की पहली झलक सामने आ चुकी है, जिसमें वह छोड़े पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म का टीजर 5 नवंबर को रिलीज होगा।

विद्या बालन को 'पनौती' मानने लगे थे लोग



फिल्म की शूटिंग में हो गया था कांड

विद्या बालन ने ये बात 'भूत भुलैया 3' फिल्म के प्रमोशन के दौरान कही। विद्या ने कहा कि 'वो वक्त करियर के शुरुआती दौर का था। उस वक्त बहुत रिजेक्शन हो रहे थे और मुझे ब्रेक नहीं मिला था। मैंने एक मलयालम फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म बीच में बंद पड़ गई। फिर उन्होंने कहा कि ये लड़की पनौती है। जब से वो इस फिल्म से जुड़ी तब से फिल्म में परेशानियां शुरू हुईं और अब ये मुझे बंद ही हो गईं। बहुत सारी फिल्मों से मैं इस वजह से निकाली गईं।' एक्ट्रेस का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है।

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूत भुलैया 3' में विद्या बालन ने वापसी की

है। फिल्म में विद्या की कमाली की एक्टिंग और उनके मुंजलिका वाले किरदार को इतने दमदार तरीके से निभाया है कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने अपने करियर के डार्क फ्रेज के बारे में बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि एक फिल्म में कुछ ऐसा हुआ कि लोग उन्हें पनौती तक बुलाने लगे थे।



'फ्रीडम एट मिडनाइट' का टीजर जारी

भारतीय सिनेमा के जाने-माने फिल्म निर्माता निखिल आडवाणी इन दिनों अपनी आगामी वेब सीरीज 'फ्रीडम एट मिडनाइट' को लेकर सुर्खियों बटोर रहे हैं। इस सीरीज में सिद्धांत गुप्ता 'पंडित जवाहरलाल नेहरू', चिराग वोहरा 'महात्मा गांधी' और राजेन्द्र चावला 'सरदार वल्लभभाई पटेल' की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अब 'फ्रीडम एट मिडनाइट' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें तमाम सितारों की झलक दिख रही है। नेहरू के किरदार में सिद्धांत खूब जंच रहे हैं।

कब और कहां देख पाएंगे सीरीज

'फ्रीडम एट मिडनाइट' का प्रीमियर 15 नवंबर, 2024 से OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर होने जा रहा है। निर्माताओं ने लिखा, 'भारत की आजादी की रोमांचक कहानी का तीसरा भाग देखें। 'फ्रीडम एट मिडनाइट' 15 नवंबर से सोनी लिव पर।' यह सीरीज लैरी कॉलिन्स और डोमिनिक लैपिएर की किताब 'फ्रीडम एट मिडनाइट' पर आधारित है, जो जल्द सोनी लिव पर प्रसारित होगी।



बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट

आशीष शेलार के सामने आरएसएस पृष्ठभूमि के राजेश शर्मा की चुनौती



BJP हरियाणा की जीत वाले फॉर्मूले से महाराष्ट्र में खिलाएगी 'कमल'



ग्रांड रिपोर्ट

धीरज सिंह

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में उठापटक की राजनीति का भयंकर दौर जारी हो गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर रखी है। वहीं इस क्रम में मुंबई के सबसे चर्चित उपनगरों में से एक बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। यहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शेलार का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के राजेश शर्मा से होने जा रहा है।

कांग्रेस ने की प्रिया दत्त की छुट्टी

बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी लगातार ही विजयी होती रही है। लेकिन बीते 10 वर्षों से इस विधानसभा सीट पर BJP कब्जा किये हुए है। अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रिया दत्त बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने राजेश शर्मा पर दांव लगाया है। जानकारी दें कि बीते दो चुनावों में प्रिया दत्त इस विधानसभा क्षेत्र में BJP को हराते हैं। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में उनकी निष्क्रियता और उनके जनसंपर्क कार्यालय को बंद करने से भी उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं।

पार्टी में राजेश शर्मा की एंट्री

तो वहीं, अब इस चुनाव में कांग्रेस ने BJP को उसी के गढ़ में भेदने के लिए न केवल अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने बल्कि हिंदू वोटों को भी अपने पाले में करने के लिए इस बार राजेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व उप महापौर राजेश शर्मा RSS पृष्ठभूमि से हैं। वे साल 2012 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ऐसे में अब राजेश शर्मा के मैदान में आने से इस सीट पर मुकाबला कड़ा हो गया है। वहीं बीते 2 सितंबर 2024 कांग्रेस की एक आंतरिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की मानें तो BJP के आशीष शेलार को 46% और कांग्रेस के राजेश शर्मा को 49% जीत की संभावना जताई गई है। कांग्रेस की हमेशा से यह दिक्कत रही कि BJP के मुंबई शहर प्रमुख आशीष शेलार से मुकाबले के लिए बड़ा कैडिडेट नहीं है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनाए गए फॉर्मूले पर काम कर रही है। क्योंकि भाजपा को हरियाणा चुनाव से जो सबक मिले हैं, वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम हैं। ऐसे में राज्य में चुनाव जीतने के लिए पार्टी उसी हिसाब से रणनीति तैयार कर रही है। तो आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है।

बांद्रा पश्चिम सीट और क्षेत्र के मतदाता

इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के 288 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से ही एक है। यह मुंबई उपनगरीय जिले में स्थित है और मुंबई उत्तर मध्य संसदीय सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक मानी जाती है। बांद्रा पश्चिम विधानसभा में अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या लगभग 8,709 है जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2.84% है। यहां अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या लगभग 2,423 है जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 0.79% है। इसी तरह यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 77,583 है जो मतदाता सूची विश्लेषण के अनुसार लगभग 25.3% है। बांद्रा पश्चिम विधानसभा में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 0 ही है जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 0% है। वहीं यहां शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 306,653 है जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 100% है। अगर 2019 के संसदीय चुनाव को देखें तो बांद्रा पश्चिम विधानसभा में कुल 306653 मतदाता हैं। साल 2019 के संसदीय चुनाव के अनुसार यहां मतदान केंद्रों की संख्या 286 है। वहीं साल 2019 के ही विधानसभा चुनाव में बांद्रा पश्चिम विधानसभा का मतदाता मतदान प्रतीशत 42.72% रहा था।



2019 विधानसभा चुनाव परिणाम

उम्मीदवार	दल	वोट	वोट (%)
आशीष शेलार	भाजपा	74816	57.11
आसिफ अहमद जकारिया	कांग्रेस	48309	36.9
नोटा	नोटा	3531	2.7
इस्तियाक बशीर जागीरदार	वीवीपी	3312	2.5

साल 2009 से 2019 तक विधानसभा के निर्वाचित विधायक

2019 विधानसभा चुनाव : आशीष शेलार, BJP
2014 विधानसभा चुनाव : आशीष शेलार, BJP
2009 विधानसभा चुनाव : (बाबा) जैउद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस

विरोधी की कमजोरी और अपनी ताकत

बीजेपी हर राज्य में चुनाव से पहले अन्य पार्टियों में संघ लगाने की कोशिश करती है। भाजपा विरोधी की कमजोरी और अपनी ताकत पर भरोसा करती है। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी का भाजपा को फायदा हुआ था। ऐसे में पार्टी को महाराष्ट्र में भी ऐसे कुछ विरोधी खेमे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर वह संघ लगाकर विरोधी पार्टी को कमजोर कर खुद की ताकत बढ़ा सकती है।

वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाना

हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने पोलिंग बूथ को मजबूत करने का काम किया था और यह तय किया था कि हर भाजपा समर्थक पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचें और वोट दें। ऐसे में महाराष्ट्र में भी भाजपा चुनाव जीतने के लिए यही रणनीति अपनाएगी। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर भाजपा अब बूथ वाइज वोटर्स पर खासकर बीजेपी समर्थकों पर फोकस कर रही है। वहीं भाजपा के एक नेता के मुताबिक हरियाणा की तुलना में महाराष्ट्र में बीजेपी का संगठन ज्यादा मजबूत है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में उसे इस रणनीति का अच्छा रिजल्ट मिलेगा।

सीटों की मैपिंग और फोकस

प्राप्त जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव से मिले सबक के हिसाब से काम कर रही है। माना जा रहा है कि भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारी करते वक़्त हर विधानसभा सीट की मैपिंग करेगी और साथ ही यह भी देखेगी कि वहां पर पार्टी की क्या स्थिति है।

जानिए आखिर कौन हैं आशीष शेलार ?

भाजपा नेता आशीष शेलार का जन्म 3 अक्टूबर 1972 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में हुआ था। वे मुंबई के मिल-मजदूर इलाके में एक चॉल सिस्टम में पले-बढ़े, उसके बाद वे अपने परिवार के साथ बांद्रा पश्चिम चले गए। शेलार ने पार्ले कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और 1992 में विज्ञान स्नातक (बीएससी) की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के जीजे आडवाणी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत स्कूल के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से की थी और बाद में कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) में शामिल हो गए, अंततः एबीवीपी के मुंबई सचिव बने।

महाराष्ट्र के सियासी समीकरण

मनोज जरांगे के 'यूटर्न' से किसे फायदा, किसे नुकसान?



महाराष्ट्र की राजनीति में एक्स फैक्टर के नाम से जाने जाने वाले मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील ने चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि मराठा आंदोलन की तरफ से जिन्होंने भी नामांकन दाखिल किया था वह अपना तक नाम वापस लें। मनोज जरांगे पाटील की इस चाल से महायुति (बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन) ज्यादा परेशान नजर आ रही है।

जरांगे-पाटील चुनाव में नहीं, तो फायदा किसे?

मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज जरांगे पाटील ने कहा, "एक समाज के बल पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। मुस्लिम और दलित समुदाय के नेताओं से हमने उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी थी, लेकिन वह नहीं मिल पाई, इसलिए इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। राजनीति हमारा खानदानी धंधा तो नहीं है। हमने किसी भी पार्टी या नेता को सपोर्ट नहीं दिया है। जो 400 पार का नारा दे रहे थे, उनका क्या हुआ आपने देखा है। मराठा समुदाय का दबदबा कायम रहेगा इसमें कोई शक नहीं। आप सभी को चुपचाप जाना है और वोट कर के वापस आना है। मराठा समुदाय ने अपनी लाइन समझ लेनी चाहिए। जो महाराष्ट्र की सियासत को जानते हैं उन्हें जरांगे पाटील की इस भाषा से काफी कुछ समझ आता है। मनोज जरांगे पाटील मराठवाड़ा से आते हैं। मराठवाड़ा में लोकसभा की 8 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जरांगे पाटील ने देवेन्द्र फडणवीस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था। इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को उठाना पड़ा। मराठवाड़ा की 8 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें महायुति हार गईं। इतना ही नहीं, मराठवाड़ा से संदे विदर्भ के युवतमाल और पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर, अहमदनगर और माढा लोकसभा चुनावक्षेत्र में भी इसका असर दिखा और वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मराठा समुदाय का गुस्से को दलित और मुस्लिम समुदाय का भी साथ मिला था। और यह वोट बैंक महायुति के हार के लिए जिम्मेदार रही।

75 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने सबसे ज्यादा विदर्भ की सीटों पर सीधा मुकाबला



विश्लेषण

अमित बूज

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) और महायुति गठबंधन चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पर इस चुनाव में सबसे ज्यादा दबाव कांग्रेस पर है। कांग्रेस जहां एमवीए का सबसे बड़ा घटक दल है, वहीं करीब छह दर्जन सीटों पर उसका सीधा मुकाबला भाजपा से है।



भाजपा से सीधे मुकाबले वाली सीटों पर ज्यादा ध्यान देगी कांग्रेस

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, खासकर विदर्भ क्षेत्र में। यहां करीब 37 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं, जो कुल 62 सीटों में से आधे से अधिक हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने विदर्भ में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे एमवीए गठबंधन को विधानसभा स्तर पर 42 सीटों पर बढ़त मिली थी।

लेकिन हाल के हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों ने कांग्रेस पर दबाव डाला है, क्योंकि उनका मानना है कि भाजपा के सामने सीधे लड़ाई में कांग्रेस की स्थिति कमजोर पड़ जाती है।

कांग्रेस के लिए विदर्भ में इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न सिर्फ

उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इसका असर पूरे महाविकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन पर भी पड़ेगा। इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए अपनी ताकत दिखाने का अवसर है, और पार्टी को एमवीए के समर्थन को कायम रखने के लिए यह सबित करना होगा कि वह भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो सकती है।

कांग्रेस को सुधारना होगा स्ट्राइक रेट

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने भाजपा के खिलाफ अपने प्रदर्शन को सुधारने की चुनौती है, खासकर उन सीटों पर जहां दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। पिछले चुनाव में उत्तरी महाराष्ट्र की सीधे मुकाबले वाली छह सीटों में से कांग्रेस ने केवल दो, मराठवाड़ा की दस में से तीन, और पश्चिमी महाराष्ट्र की सात में से दो सीटों पर ही जीत हासिल की थी। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को अपनी जीत का स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, इस बार पार्टी ने चुनावी वादों को हर मतदाता तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिससे उनकी चुनावी स्थिति मजबूत हो सके। इसके साथ ही, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की योजना बनाई गई है। पार्टी के बड़े नेता विदर्भ में प्रचार के लिए उतारकर भाजपा के प्रभाव वाले इलाकों में समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस की यह रणनीति इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भाजपा से सीधी टक्कर है।

2019 में भाजपा ने मारी थी बाजी

2019 के चुनाव में विदर्भ की 31 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला हुआ था। इनमें से 23 पर भाजपा और 8 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। इसलिए, दोनों पार्टियां इस क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक रही हैं। दिलचस्प है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रदेश अध्यक्ष इसी क्षेत्र हैं। यह देवेन्द्र फडणवीस और विजय वेड्टीवार का भी क्षेत्र है। इसी तरह पिछले चुनाव में मुंबई में कांग्रेस और भाजपा 12 सीटों पर आमने-सामने थी। इनमें से कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीती थी।